वर्ष 13 • अंक 38 • 8 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

शनिवार 4 अप्रैल 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 8

बिग बास्केट और ग्रोफर्स करेंगी भर्तियां

संजीव मेहता पृष्ठ 2

बाजार पूंजीकरण में एचयूएल ने एचडीएफसी को पीछे छोड़ा

डॉलर रु. 76.20 ▲ 0.60 रुपये | यूरो रु. 82.20 ▼ 0.60 रुपये | सोना (10ग्राम) रु. 43760 ▲ 460 रुपये | सेंसेक्स 27590.90 ▼ 674.40 | निफ्टी 8083.80 ▼ 170.70 | निफ्टी फ्यूचर्स 8084.50 ▲ 00.70 | ब्रेंट क्रूड 29.80 डॉलर ▲ 460.00 डॉलर

एक नज़र

दुनिया भर में कोरोना से 53 हजार से ज्यादा की मौत

दुनिया भर में कोरोनावायरस के मामले दस लाख से अधिक हो गए हैं, जबकि 53 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के देशों द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर के 188 देशों में कोरोना वायरस से संक्रमण (कोविड-19) के दस लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 53 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में पिछले 24 घंटे में 900 लोगों की मौत हुई है, वहीं ब्रिटेन में 684 लोगों की मौत हुई है।

तबलीगी के 960 विदेशियों के नाम काली सूची में डाले

तबलीगी जमात के जिन 960 विदेशी कार्यकर्ताओं के नाम काली सूची में डाले गए हैं उनमें चार अमेरिकी, नौ ब्रिटिश और छह चीनी नागरिक शामिल हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन सभी के पर्यटक वीजा रद्द कर दिए हैं। इनमें से कुछ के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस बीच, देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,547 हो गई है जबकि 62 की मौत हुई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि पृथक केंद्रों को स्थापित करने के लिए राज्यों को 11,092 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी है।

बॉन्ड व मुद्रा बाजार में 2 बजे तक ही कारोबार

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि बॉन्ड व मुद्रा बाजार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बजाय 10 बजे से 2 बजे तक परिचालन में रहेगा और नई समयसारणी 7 से 17 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। आरबीआई ने कहा कि कोरोनावायरस से जुड़ी अव्यवस्था के कारण यह फैसला लिया गया है। बाजारों का सामान्य समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे का है, जो प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग पर निर्भर है। उदाहरण के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में रीपो सुबह 9 बजे से 2.30 बजे तक उपलब्ध है, वहीं कॉरपोरेट बॉन्ड में रीपो शाम 6 बजे बंद होता है। अब सबकुछ 2 बजे बंद हो जाएगा।

ओपेक प्लस देशों की बैठक 6 अप्रैल को

प्रमुख कच्चे तेल उत्पादक व निर्यातक देशों के मंच ओपेक और रूस की अगुआई वाले अन्य प्रमुख खनिज तेल उत्पादक देशों के समूह की बैठक सोमवार 6 अप्रैल को होगी। ओपेक से जुड़े एक सूत्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी। दुनिया के प्रमुख कच्चे तेल के उत्पादक सऊदी अरब ने गुरुवार को ओपेक तथा अन्य प्रमुख तेल निर्यातक देशों की बैठक बुलाने का आह्वान कर सभी को हैरान कर दिय था। रूस के साथ कीमत युद्ध के बीच घटाने की होड़ में लगे सऊदी अरब ने अब कहा है कि वह वह कच्चे तेल के बाजार में स्थिरता लाना चाहता है।

एडीबी का भारत की वृद्धि दर 4 फीसदी रहने का अनुमान

वैश्विक महामारी के कारण दुनिया भर में पैदा हुए स्वास्थ्य आपात के बीच, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर चार फीसदी रह सकती है। साथ ही इस बहुपक्षीय संस्था ने अपने प्रमुख प्रकाशन- एशियाई विकास परिदृश्य में कहा कि व्यापक आर्थिक बुनियाद मजबूत होने से भारत अगले वित्त वर्ष में जोरदार वापसी करेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का अनुमान है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 में 5 प्रतिशत रहेगी।

व्यापार गोष्ठी

लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर कितना असर?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरु हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें gosthi@bsmail.in अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या उद्योगों को मिलना चाहिए प्रोत्साहन पैकेज

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**

आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या सरकार की पहल से दाल	हां	42.86%
मिलों की घटेगी मुश्किल?	नहीं	57.14%

लॉकडाउन और कारोबार को लेकर उद्योग जगत के सीईओ की राय

राहत मिले और लॉकडाउन घटे

सुरजीत दास गुप्ता और देव चटर्जी
नई दिल्ली/मुंबई, 3 अप्रैल

भारतीय उद्योग जगत में इस बात को लेकर करीब-करीब आम राय है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सरकार द्वारा घोषित राहत उपाय नाकाफी हैं। उसकी मांग है कि सरकार को कोविड-19 के कारण कारोबार को हुए नुकसान से निपटने के लिए एक व्यापक राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।

विभिन्न क्षेत्र की 25 बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारियों के बीच कराए गए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई हैं। इनमें वित्तीय सेवा से लेकर बैंक, ऊर्जा, वाहन, बंदरगाह, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीए इंटरनेट और रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनियां और कई बड़े कारोबारी समूह शामिल हैं।

सर्वेक्षण में शामिल 96 फीसदी मुख्य कार्याधिकारियों ने कहा कि ऋण के भुगतान पर तीन महीने की छूट की अवधि बढ़ाकर कम से कम एक साल की जानी चाहिए। इसे दो साल भी किया जा सकता है। 92 फीसदी मुख्य कार्याधिकारियों का कहना था कि इस संकट से निपटने के लिए कंपनियों से फिलहाल कर नहीं लिया जाना चाहिए या उनके आय कर में कटौती की जानी चाहिए।

सभी मुख्य कार्याधिकारियों ने एक सुर में सरकार से उद्योग जगत के लिए पैकेज देने की मांग की। कई मुख्य कार्याधिकारियों का कहना है कि

ऋण भुगतान स्थगन को 3 महीने से आगे बढ़ाया जाए	हां : 96 फीसदी नहीं : 4 फीसदी पता नहीं : –	मंदी या ऋणात्मक वृद्धि का अंदेशा है	हां : 40 फीसदी नहीं : 60 फीसदी पता नहीं : –
उद्योग के लिए प्रोत्साहन पैकेज चाहते है	हां : 100 फीसदी नहीं : पता नहीं : –	लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद हटा लेना चाहिए	हां : 52 फीसदी नहीं : 28 फीसदी पता नहीं : 20 फीसदी
मंदी या ऋणात्मक वृद्धि का अंदेशा है	हां : 40 फीसदी नहीं : 60 फीसदी पता नहीं : –	वेतन में कटौती या छंटनी करेंगे	हां : 12 फीसदी नहीं : 60 फीसदी पता नहीं : 28 फीसदी

ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के नियमों में ढील दी जानी चाहिए। दिवालिया कार्यवाही को लॉकडाउन हटने के बाद अगले छह महीने तक टालना चाहिए।

टीवीएस के प्रबंध निदेशक वेणु श्रीनिवासन ने कहा, 'ऋण भुगतान पर मिली छूट को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इससे ज्यादा जरूरी यह है कि एनपीए के नियमों में ढील दी जाए। अन्यथा एनबीएफसी उद्योग चौपट हो जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मझोली कंपनियों के लिए आईबीसी कार्यवाही को छह महीने के लिए टाल देना चाहिए।'

आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए कहा, 'सरकार को मांग बहाल करने के लिए पैसे झोंकने चाहिए। लेकिन उद्योग कर, पीएफ और ईएसआईसी जैसे वैधानिक बकायों के भुगतान में राहत चाहता है। साथ ही रोजगार से जुड़े नियमों में भी ढील दी जानी चाहिए और कार्यशील पूंजी की सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी की जानी चाहिए।' सरकार कंपनियों को राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है लेकिन वे उससे कहीं व्यापक पैकेज की मांग कर रही हैं। कई क्षेत्रों में कारोबार करने वाली एक कंपनी के प्रबंध निदेशक ने कहा, 'कुल पैकेज 100 अरब डॉलर का होना चाहिए। पहले गरीबों को फिर खुद का रोजगार करने वालों को और इसके बाद छोटी तथा मझोली कंपनियों के लिए इसकी घोषणा की जानी चाहिए। इस तरह सभी को इस संकट की स्थिति में सरकार की तरफ से राहत मिलनी चाहिए। बंदरगाह क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी के सीईओ ने कहा कि देश की जीडीपी में योगदान करने वाले सभी घटकों को जीडीपी का 10 से 15 फीसदी हिस्सा राहत के रूप में दिया जाना चाहिए।' इस बात पर सीईओ बंटे हुए हैं कि देश में मंदी आएगी या नहीं। हालांकि इस बात पर सभी एकमत हैं कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती जरूर आएगी।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

लाइट बंद करने से बिजली क्षेत्र सतर्क

श्रेया जय
नई दिल्ली, 3 अप्रैल

लॉकडाउन के दौरान एकजुटता दिखाने के लिए रविवार को लाइट बंद करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बिजली मंत्रालय हरकत में आ गया है क्योंकि इससे बिजली की मांग में अचानक भारी कमी का अंदेशा है। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि इससे नैशनल पावर ग्रिड पर कोई खास असर नहीं होगा और इसके लिए पहले से ही योजना बनाई जाएगी।

मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, 'बिजली मंत्री आर के सिंह ने इस मुद्दे पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ग्रिड ऑपरेटर पावर सिस्टम ऑपरेटर कॉरपोरेशन से आज की बैठक में बात की। उन्हें पूरा विश्वास है कि इस आयोजन के कारण ग्रिड में अचानक आने वाले उतार चढ़ाव को संभाल लिया जाएगा।'

अलबत्ता, एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इससे मांग में कम से कम उतार चढ़ाव की उम्मीद है। उन्होंने कहा, 'हमने सभी राज्यों और क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों को इसके लिए पहले से तैयारी करने को कहा है।' मोदी ने लोगों से लाइट बंद करने का आह्वान ऐसे समय किया है जब लॉकडाउन के कारण पिछले दो हफ्तों से बिजली की मांग में अभूतपूर्व कमी आई है। कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद मार्च में बिजली की मांग में करीब 30 फीसदी की गिरावट आई है। यह लॉकडाउन 14 अप्रैल तक रहेगा।

देश के पांच क्षेत्रों में स्थित लोड डिस्पैच केंद्र अपने इलाकों में बिजली आपूर्ति के सभी पहलुओं पर नजर रखते हैं। अधिकारियों ने कहा कि अभी व्यस्त घंटों में बिजली की मांग करीब 120 से 125 गीगावाट है जिसमें घरों में रोशनी के लिए आपूर्ति करीब 12 से 15 गीगावाट है। एक अधिकारी ने कहा कि घरों में बत्ती बुझाने से लोड में 12.15 फीसदी की कमी आएगी।

मांग में भारी कमी और उत्पादन क्षमता बंद होने की आशंका को देखते हुए बिजली क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों में पिछले एक पखवाड़े से आपात स्थिति जैसे हालात हैं। इनमें उत्पादक कंपनियां, आपूर्तिकर्ता और ग्रिड जेनरेटर कंपनियां शामिल हैं। हालांकि रविवार के बत्ती गुल आयोजन में देश के पावर ग्रिड में अचानक होने वाले उतारचढ़ाव को संभालने का जिम्मा पीओएसओसीओ का होगा। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि पीओएसओसीओ ने अपने क्षेत्रीय और राज्य लोड डिस्पैच केंद्रों को कुछ ही मिनट के भीतर बिजली की मांग में भारी कमी और फिर अचानक तेजी के लिए तैयार रहने को कहा है।

रविवार रात नौ बजे दीये जलाएं

कोरोनावायरस को पराजित करने की देश की सामूहिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देशवासियों से अपील की कि वे रविवार 5 अप्रैल को रात नौ बजे अपने घरों की बालकनी में खड़े रहकर मोमबत्ती, दीया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं।

प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए अपने 11 मिनट से ज्यादा के वीडियो संदेश में इस दौरान लोगों से सामाजिक दूरी को बनाए रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी बनाए रखने की लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघे क्योंकि कोरोना की शृंखला को तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'मेरी प्रार्थना है कि इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों या मोहल्लों में नहीं जाना है, अपने घर के दरवाजे और बालकनी से ही इसे करना है। उन्होंने कहा कि इस रविवार, 5 अप्रैल को, हम सबको मिलकर, कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है।

एसआईपी से किनारा कर रहे निवेशक

जश कृपलानी
मुंबई, 3 अप्रैल

कोरोनावायरस संकट और इसके बाद देश में लॉकडाउन की घोषणा से म्युचुअल फंड निवेशक भी सांसत में आ गए हैं। मौजूदा आर्थिक सुस्ती के बीच इन निवेशकों की आय पर भी असर हुआ है और वे सिस्टैमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी), बंद करने या इसमें निवेश अस्थायी तौर पर रोकने के बारे में सोचने लगे हैं। सलाहकारों का मानना है कि शेयरों से मामूली लाभ और लॉकडाउन के बीच आय कम होने की आशंका से से निवेशकों के समक्ष एसआईपी रोकने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं रह गया है। प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेस के संस्थापक अमोल जोशी ने कहा, 'विमानन एवं होटल उद्योगों के कर्मचारियों पर कोरोना संकट का सबसे अधिक असर हुआ है। इनकी आय प्रभावित होने से इन क्षेत्रों के कर्मचारियों ने एसआईपी निवेश रोकने पर विचार शुरू कर दिया है। इस दौरान कुछ कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती हुई है।'

शेयर बाजार में गिरावट से भी म्युचुअल फंड निवेशकों को खासा नुकसान हुआ है। फरवरी में सेंसेक्स में करीब 6 प्रतिशत गिरावट आई थी, जो मार्च में 23 प्रतिशत तक फिसल गया। मोटे अनुमान के अनुसार 85 से 90 प्रतिशत एसआईपी निवेवकों की रकम शेयरों में लगाई गई थी।

मुंबई स्थित तेजस कंसल्टैंसी के सह-संस्थापक रीतेश षेठ ने कहा, 'निवेषक भविष्य में अपनी आय की संभावनाओं को लेकर सशंकित हैं। वेतनभोगी और स्व-रोजगार में लगे दोनों तरह के लोगों में इस तरह की चिंता है। ऐसे में उन्हें लग रहा है कि फिलहाल एसआईपी रोक देना ठीक रहेगा।'

एसआईपी मासिक निवेश योजनाएं होती हैं, जिनकी वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच खासी लोकप्रियता है। इनके तहत निवेशक एकमुश्त रकम के बदले थोड़ी-थोड़ी मात्रा में निवेश करते हैं।

म्युचुअल फंड उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि मार्च में एसआईपी के जरिये रकम आनी जारी रहेगी, लेकिन अप्रैल में इसमें गिरावट आ सकती है। कारोबारियों के अनुसार म्युचुअल फंड कंपनियों की नजरें अप्रैल के आंकडों पर रहेंगी। एक फंड कंपनी के अधिकारी ने कहा कि मार्च में एसआईपी के जरिये 8,000-8,200 करोड़ रुपये का निवेश आ सकता है लेकिन अप्रैल में निवेश में कमी आ सकती है।

दीपक शर्मा

- आर्थिक सुस्ती के बीच निवेशक एसआईपी रोकने पर कर रहे विचार
- विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारी भविष्य में अपनी आय को लेकर चिंतित
- विमानन एवं होटल उद्योग के कर्मचारियों की आय पर पड़ी है खासी मार

इस हफ्ते 6.4 फीसदी लुढ़का बाजार

कोरोना के प्रसार और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित निवेशकों की ओर से बिकवाली जारी रहने से घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को 2 फीसदी टूट गया। सेंसेक्स 674 अंक गिरकर 27,591 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 170 अंक नीचे 8,084 पर बंद हुआ। इस हफ्ते बेंचमार्क सूचकांकों में 6.4 फीसदी की गिरावट आई है। आरबीआई ने हाल में कुछ राहत की घोषणाएं की हैं लेकिन विशेषज्ञों ने कहा कि अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को देखते हुए और ज्यादा प्रोत्साहन की जरूतर है। इक्विनॉमिक्स के संस्थापक जी चोकालिंगम ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन के बाद चीजें सामान्य हो जाएंगी लेकिन अब लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी तमाम तरह की बंदिशें लगाए जाने के संकेत हैं। इसका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। *बीएस*

राज्यों ने निजी अस्पतालों को भी तैयार रहने को कहा

सोहिनी दास, विनय उमरजी और गिरीश बाबू
मंबई/अहमदाबाद/चेन्नई, 3 अप्रैल

देश में कोरोनावायरस से संक्रमित मामलों की संख्या 2,000 से काफी आगे निकल गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मामले अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो मध्य मई आते-आते देश में ऐसे मरीजों की संख्या 13 लाख तक पहुंच सकती है।

आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2018 तक भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में 7,39,024 बेड उपलब्ध थे। इनके अलावा रक्षा अस्पतालों में करीब 35,000 बेड हैं, साथ ही रेलवे के अस्पतालों में भी करीब 14,000 बेड उपलब्ध हैं। मोटे अनुमान के अनसार देश के निजी अस्पतालों में करीब 30 लाख बेड उपलब्ध हैं। वर्ष 2018 में 3,740 लोगो की मौत सांस की गंभीर बीमामी से हो गई थी जबकि 4,213 लोगों को निमोनिया के कारण अपनी जान गंवानी पडी थी। नैशनल हेल्थ प्रोफाइल, 2019 के अनुसार सांस की गंभीर बीमारी के करीब 4 करोड़ मामले आए थे और करीब 9,28,485 मामले उसी साल निमोनिया के भी दर्ज हुए थे। कोविड-19 से हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। संक्रमण की गंभीर आशंका वाले क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के इलाज के लिए सरकार के पास पर्याप्त स्वास्थ्य ढाचा उपलब्ध नहीं है, ऐसे में राज्य सरकारें विकराल होती स्थिति से निपटने के लिए हाथ-पांव मार रही हैं और अब वे निजी अस्पतालों को भी तैयार रहने के लिए कह रही हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कुछ जिलों में निजी अस्पतालों को भी कोविड-19 से निपटने की मुहिम शामिल करने

फोटोः पीटीआई

- स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार करने में जुटे राज्य
- निजी अस्पतालों की भी लेंगे मदद
- अपोलो सहित कई अस्पतालों को तैयार रहने के दिए निर्देश

के आदेष दिए गए हैं। सार्वजनिक-निजी ढांचे पर आधारित अस्पतालों जैसे दिल्ली में इंद्रप्रस्थ अपोलो आदि को कोविड-19 से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा गया है। हालांकि अपोलो से स्वतंत्र रूप इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई।

मुंबई के अंधेरी में 500 बेड वाले सेवन हिल्स हॉस्पिटल को पहले ही कोविड-19 से निपटने वाला अस्पताल करार दे दिया गया है। यहां ऐसे मरीजों के इलाज के लिए इंतजाम किए गए हैं। इस बारे में अस्पताल के प्रवक्ता ने कहा, 'हम इस अस्पताल में 100 बेड की सुविधा तैयार करने में सरकार की मदद कर रहे हैं।'

रिलायंस ने भी पुणे-मुंबई राजमार्ग पर अपना एक छोटा संयंत्र कोविड-19 के मरीजों के लिए सुरक्षित कर लिया है। जिलों में यह संकट ज्यादा गहरा है जहां घर लौटे प्रवासी कामगारों में इसके लक्षण शुरू होने के बाद स्थिति विकराल हो सकती है। आशंका है कि शहरों से गांवों में लौटे हरेक 10 प्रवासी कामगारों में से तीन अपने साथ यह वायरस ले गए हैं।

महाराष्ट्र में कोविड-19 संक्रमण के 400 से अधिक मामले सामने आए हैं। मुंबई में दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती माने जाने वाली धारावी में कोविड के मरीज सामने आने से स्थानीय प्रशासन इसके सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए दिन-रात काम कर रहा है। 2 वर्ग किमी में फैली इस बस्ती में करीब 8 लाख लोग रहते हैं। मुंबई के तीन सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में भी कोविड के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं।

(शेष पृष्ठ 8 पर)

संक्षेप में

क्रिसिल ने वेदांत की रेटिंग घटाई

क्रिसिल ने वेदांत लिमिटेड के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पर अपने रेटिंग परिदृश्य को 'स्टेबल' से घटाकर 'निगेटिव' कर दिया है। परिदृश्य में संशोधन कोविड-19 महामारी के बीच वित्त वर्ष 2021 में ब्रेंट क्रूड, जस्ता और एल्युमीनियम की कमजोर कीमतों के जोखिम की वजह से किया गया है। इसके अलावा एल्युमीनियम तथा जस्ता कीमतों में सुस्ती तथा बिक्री में नरमी की वजह से वित्त वर्ष 2020 के लिए कंपनी का परिचालन लाभ भी कमजोर पड़ा है। *बीएस*

ऑर्किड फार्मा ने धानुका के विलय को मंजूरी दी

ऑर्किड फार्मा लिमिटेड (ओपीएल) की निगरानी समिति ने धानुका फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (डीपीपीएल) के कंपनी में विलय की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस विलय के तहत ओपीएल के 10 रुपये की कीमत के 10,000 इक्विटी शेयर डीपीपीएल के शेयरधारकों को जारी किए जाएंगे। यह धानुका की समाधान योजना का एक हिस्सा है। समाधान योजना के तहत धानुका लैबोरेटरीज ने ओपीएल में 370 करोड़ रुपये तथा लगभग 40 करोड़ रुपये की अन्य पूंजी लगाई है। उसने 200 करोड़ रुपये भी निर्धारित किए हैं, जिन्हें एक साल में खर्च किया जाएगा। *बीएस*

गूगल भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए देगी रकम

गूगल भारत समेत दुनियाभर में कोरोनावायरस से जुड़ी भ्रामक जानकारियों से निपटने पर 65 लाख डॉलर (करीब 49 करोड़ रुपये) की राशि खर्च करेगी। कंपनी इस राशि से कोरोनावायरस महामारी से जुड़े तथ्यों की सच्चाई जांचने वालों (फैक्ट चेकर्स) और गैर-लाभकारी संगठनों की मदद करेगी। गूगल ने शुक्रवार को अपने एक ब्लॉग में कहा कि स्वास्थ्य अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि सूचनाओं की अधिकता से लोगों के लिए इस महामारी के बारे में विश्वसनीय जानकारी जुटाना मुश्किल हो जाएगा। *भाषा*

बिड़ला समर्थित फाउंडेशन से जारी किया टोलफ्री नंबर

मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था एमपावर ने कोरोनावायरस महामारी की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यकताओं से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के सहयोग से एक टोलफ्री हेल्पलाइन- 1800 120 820050 - जारी की है। इस हेल्पलाइन को 'बीएमसी-एमपावर 1ऑन1' नाम दिया गया है और यह सातो दिन चौबीसो घंटे उपलब्ध रहेगा। *बीएस*

बाजार पूंजीकरण में एचयूएल आगे

एचडीएफसी बैंक से आगे निकली कंपनी, बजाज फाइनैंस शीर्ष 10 की सूची से बाहर

कृष्णकांत
मुंबई, 3 अप्रैल

- एचयूएल का बाजार पूंजीकरण अब 4.66 लाख करोड़ रुपये हुआ
- एचडीएफसी का बाजार पूंजीकरण 4.46 लाख करोड़ रुपये
- 20 फरवरी के बाद उपभोक्ता वस्तु कंपनी महज 4.2 फीसदी फिसली जबकि एचडीएफसी का बाजार पूंजीकरण 33 फीसदी घटा

उपभोक्ता वस्तु बनाने वाली देश की सबसे मूल्यवान कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) बाजार पूंजीकरण के मोर्चे पर एचडीएफसी बैंक को पछाड़कर आगे निकल गई है। गुरुवार के बंद भाव के अनुसार, एचयूएल का बाजार पूंजीकरण 4.66 लीख करोड़ रुपये हो गया जबकि एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 4.46 लाख करोड़ रुपये रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) और टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज (टीसीएस) इस सूची में शीर्ष पर बरकरार रहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 6.83 लाख करोड़ रुपये रहा जबकि टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज का बाजार पूंजीकरण 6.21 लाख करोड़ रुपये हो गया।

ब्रिटेन की कंपनी यूनिलीवर की भारतीय सहायक कंपनी एचयूएल के शेयर का प्रदर्शन कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण प्रभावित शेयरों में सबसे अच्छा रहा। कंपनी का बाजार पूंजीकरण में 20 फरवरी 2020 के बाद महज 4.2 फीसदी की गिरावट आई जबकि कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के कारण आर्थिक व्यवधान की आशंका में व्यापक बाजार में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई।

इसके मुकाबले एचडीएफसी बैंक के बाजार पूंजीकरण में 20 फरवरी 2020 के बाद 33.1 फीसदी की जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। जबकि इस दौरान निफ्टी50 सूचकांक में शामिल कंपनियों के एकीकृत बाजार पूंजीकरण में 31.2 फीसदी की गिरावट आई। निफ्टी50 शेयरों का एकीकृत बाजार पूंजीकरण अब घटकर 62.44 लाख करोड़ रुपये रहा गया जो 20 फरवरी 2020 को बाजार बंद होने पर 90.77 लाख करोड़ रुपये था।

कोरोवायरस के फैलने के कारण आर्थिक व्यवधान की आशंका में दलाल स्ट्रीट पर कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में काफी उलटफेर दिखा। लेनदारों की रैंकिंग फिसलने लगी और उपभोक्ता वस्तु एवं औषधि क्षेत्र के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र की अब दो कंपनियां- एचयूएल और आईटीसी- शामिल हो गई हैं। खुदरा ऋण देने वाली कंपनी बजाज फाइनैंस अब शीर्ष 10 की सूची से बाहर हो गई है और उसका बाजार पूंजीकरण नेस्ले और एशियन पेंट्स से भी कम हो गया है।

विश्लेषकों का कहना है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी का बैंकों पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है जबकि एचयूएल जैसी ऋण मुक्त कंपनियों पर उसका कोई खास प्रभाव नहीं दिखा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि निकट भविष्य में यही प्रवृत्ति बरकरार रहेगी। विश्लेषकों का कहना है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी का बैंकों पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है जबकि एचयूएल जैसी ऋण मुक्त कंपनियों पर उसका कोई खास प्रभाव नहीं दिखा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि निकट भविष्य में यही प्रवृत्ति बरकरार रहेगी।

भारत बायोटेक बना रही कोरोनावायरस का टीका

बीएस संवाददाता
हैदराबाद, 3 अप्रैल

टीका बनाने वाली हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने आज कहा कि वह कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीका बनाने वाली वायरोलॉजिस्ट एवं टीका कंपनियों के अंतरराष्ट्रीय सहयोग में शामिल है। इसके तहत नाक के जरिये लगाई जाने वाला कोविड-19 के अनोखे टीका क्लोरोफ्लू के विकास और परीक्षण पर काम चल रहा है।

क्लोरोफ्लू टीका बनाने वाली कंपनी फ्लूजेन की वैक्सिन कैंडिडेट एम2एसआर पर आधारित होगा जो इन्फ्लूएंजा वायरस का सेल्फ-लिमिटिंग संस्करण है और यह बुखार के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रेरित करता है। फ्लूजेन की प्रयोगशाला एम2एसआर में कोरोनावायरस की जीन शृंखला सार्स:-कोव-2 को डालेगी ताकि नया टीका उस रोगजनक के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ले।

भारत बायोटेक के प्रमुख (कारोबार विकास) राशेज एला ने इस साझेदारी के बारे में बताते हुए कहा, 'भारत बायोटेक इस टीके का उत्पादन करेगी। कंपनी इसका क्लीनिकल परीक्षण करेगी और वैश्विक वितरण के लिए करीब 30 लाख टीके का उत्पादन करेगी। इस साझेदारी अनुबंध के तहत फ्लूजेन अनी मौजूदा विनिर्माण प्रक्रियाओं का हस्तांतरण भारत बायोटेक को करेगी ताकि वह इस टीके के क्लीनिकल परीक्षण के लिए समर्थ हो सके।'

कंपनी ने कहा है कि क्लोफ्लू टीके की अवधारणा को नए सिरे से ढालने और यूडब्ल्यू-मैडिसन के प्रयोगशाला जंतु मॉडल में इसके परीक्षण में 3 से 6 महीने का समय लगने की उम्मीद है। उसके बाद भारत बायोटेक मानव पर सुरक्षित एवं कुशल परीक्षण के लिए उसका उत्पादन करेगी। कंपनी ने कहा कि क्लोरोफ्लू का मानव पर परीक्षण 2020 के अंत तक होने की उम्मीद है।

सीईओ चाहे व्यापक राहत पैकेज

पृष्ठ-1 का शेष

सर्वेक्षण में शामिल 40 फीसदी सीईओ का कहना है कि मंदी अपरिहार्य है जबकि बाकी का इस बारे में सकारात्मक रुख है और उनका मानना है कि जीडीपी की विकास दर 1 से 3 फीसदी तक रह सकती है।60 फीसदी मुख्य कार्याधिकारियों ने कहा कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती या छंटनी नहीं करेंगे लेकिन 12 फीसदी का कहना है कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बाकी सीईओ का कहना है कि वे अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं और इसका फैसला आने वाले दिनों में परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।हालांकि सर्वेक्षण में शामिल 52 फीसदी मुख्य कार्यकारी इस बात पर सहमत थे कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन को आंशिक रूप से हटा दिया जाना चाहिए। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई चर्चा से लगता है कि लॉकडाउन के चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सकता है। लेकिन कई सीईओ का कहना है कि जिंदगी कारोबार से ज्यादा अहम है। 28 फीसदी सीईओ ने कहा कि लॉकडाउन और 15 दिन रहना चाहिए।एक प्रमुख इंटरनेट कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा, 'मुझे आश्चर्य है कि कई सीईओ लोगों की जिंदगी बचाने पर जोर देने के बजाय कारोबार शुरू करने की बात कर रहे हैं।' लॉकडाउन में आंशिक छूट देने की वकालत कर रहे सीईओ ने इसे चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए अलग-अलग सुझाव दिए हैं। वित्तीय सेवा क्षेत्र की एक कंपनी के सीईओ ने कहा, 'शहरों और राज्यों में मुख्य सड़कों पर यातायात की अनुमति होनी चाहिए ताकि प्रवासी अपने घर जा सकें। साथ ही बड़ी औद्योगिक कंपनियों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनों को अपना कामकाज शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसने मजदूरों और छोटे दुकानदारों को रोजगार मिलता है। मॉल नहीं खुलने चाहिए।' अन्य मुख्य कार्याधिकारियों ने शहरों में औद्योगिक क्षेत्रों को खोलने का सुझाव दिया।

श्रमिक किल्लत से जूझ रहीं इस्पात कंपनियां

ईशिता आयान दत्त
कोलकाता, 3 अप्रैल

प्रमुख चुनौतियां

- ट्रकों पर माल को लादने और उतारने के लिए मजदूरों की किल्लत
- गोदाम अथवा ग्राहकों के गंतव्य के लिए आवाजाही पर पाबंदी से चुनौती
- कच्चे माल और तैयार वस्तुओं की आपूर्ति में व्यवधान
- टाटा स्टील ने बुधवार को घोषणा की थी कि वह जमशेदपुर, कलिंगनगर, अंगुल और गमहरिया के अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों में उत्पादन घटा रही है
- कंपनी ने इन संयंत्रों को रखरखाव एवं देखभाल के मोड में रखा है

कोरोनावायरस (कोविड-19) वैश्विक माहामारी के प्रसार को रोकने के लिए 21 दिनों की देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर परिचालन घटाने वाली प्रमुख इस्पात कंपनियों को अब श्रमिकों की किल्लत जैसी समस्या से जूझना पड़ रहा है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों ने ट्रकों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की है लेकिन ट्रकों पर माल के लदान के लिए श्रमिकों का अभाव एक प्रमुख चुनौती बन गई है। परिणामस्वरूप कच्चे माल और तैयार वस्तुओं की आवाजाही को झटका लगा है।

अधिकतर इस्पात कंपनियां 40 से 60 फीसदी उत्पादन क्षमता पर अपने संयंत्रों का परिचालन कर रही हैं। उत्पादन के इस स्तर को बरकरार रखना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती दिख रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) के सूत्रों ने कहा, ट्रकों की आवाजाही में ढील दी गई है लेकिन माल को लादने और उतारने के लिए लोग उपलब्ध नहीं हैं।

पिछले सप्ताह सेल ने कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर अपने संयंत्रों में तात्कालिक व्यवधान की बात कही थी। सूत्रों ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की यह दिग्गज इस्पात कंपनी फिलहाल 60 फीसदी क्षमता पर उत्पादन कर रही है और वह उत्पादन में धीरे-धीरे कमी लाएगी। इस्पात क्षेत्र के एक अन्य सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय इस्पात निगम (आरआईएनएल) के सूत्रों ने कहा कि इस अप्रत्याशित परिस्थिति में तैयार उत्पादों की आवाजाही कई करणों से प्रभावित हुई है जैसे अधिकतर रेक को आम लोगों के लिए वस्तुओं की आपूर्ति में लगाना। कंपनी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण कुछ जगहों पर श्रमिकों की किल्लत हो गई है। लेकिन जहां तक कच्चे माल का सवाल है तो फिलहाल कोई खास समस्या नहीं है।

श्रमिकों की किल्लत और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी परामर्श के मद्देनजर आरआईएनएल ने भी अपने ब्लास्ट फर्नेस को तात्कालिक तौर पर बंद करते हुए उत्पादन कम कर दिया है। आरआईएनएल सूत्रों के अनुसार, फिलहाल क्षमता उपयोगिता करीब 60 से 65 फीसदी के दायरे में है।

देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा किए जाने के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील सहित सभी प्रमुख इस्पात कंपनियों ने उत्पादन में कटौती की है। टाटा स्टील ने बुधवार को घोषणा की थी कि वह जमशेदपुर, कलिंगनगर, अंगुल (टाटा स्टील बीएसएल) और गमहरिया (टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्शन) के अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों में उत्पादन घटा रही है। कंपनी ने इन संयंत्रों को रखरखाव एवं देखभाल के मोड में रखा है। आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया भी न्यूनतम उत्पादन स्तर पर परिचालन कर रही है।

ब्लास्ट फर्नेस को बंद करना कोई विकल्प नहीं है क्योंकि इसे दोबारा शुरू करने में एक से डेढ़ महीने लग सकते हैं। सूत्रों बताया कि इसमें लागत भी 250 से 300 करोड़ रुपये तक आ सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों ने स्पष्ट किया है कि खनन, इस्पात, कोयला, बिजली, उर्वरक आदि आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आते हैं और इसलिए लॉकडाउन की अवधि में भी इन क्षेत्रों के संयंत्रों का परिचालन जारी रहेगा।

जिंदल स्टील ऐंड पावर के प्रबंध निदेशक वीआर शर्मा ने कहा कि ट्रकों की आवाजाही की अनुमति देने संबंधी केंद्र सरकार का निर्णय स्वागतयोग्य है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ठेकेदारों और माल लादने एवं उतारने वाले श्रमिकों की कमी हो रही है। उन्होंने कहा, 'उन्हें न्यूनतम क्षमता पर काम करने की अनुमति देनी चाहिए।'

निविया इंडिया बना रही हैंड सैनिटाइजर

विनय उमरजी
अहमदाबाद, 3 अप्रैल

कोविड-19 (कोरोनावायरस) के प्रकोप से निपटने में मदद करने के लिए स्किनेकेयर उत्पाद बनाने वाले प्रमुख कंपनी निविया इंडिया ने घोषणा की है कि कंपनी ने अहमदाबाद के समीप अपने साणंद संयंत्र में हैंड सैनिटाइजर का उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वितरण के लिए अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उत्पादन किया जा रहा है।

कंपनी के साणंद संयंत्र में स्किनकेयर उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है। कंपनी इस संयंत्र में फिलहाल हैंड सैनिटाइजर बनाने का निर्णय लिया है। कंपनी सैनिटाइजर की आपूर्ति अहमदाबाद और वड़ौदा के सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के अलावा देश भर में कंपनी के वितरण साझेदारों को किया जाएगा। यह पहल हैंड सैनिटाइजर की कमी को देखते हुए की गई है क्योंकि कोरोनावायरस के प्रकोप के मद्देनजर फिलहाल यह एक प्रमुख एवं आवश्यक उत्पाद बन चुका है।

निविया इंडिया ने एक बयान में कहा, 'हैंड सैनिटाजर की कमी को देखते हुए कंपनी ने अपने प्रमुख साझेदारों के सामूहिक सहयोग से हैंड सैनिटाइजर बनाने की पहल की है। इसका उत्पादन हमारे गुजरात संयंत्र में किया जाएगा। वहां से उत्पादित हैंड सैनिटाइजर की उन तीन सरकारी अस्पतालों को मुफ्त आपूर्ति की जाएगी जो शहर को कोविड-19 के खिलाफ जंग में अग्रणी हैं।' इसके अलावा कंपनी देश भर में अपनी आपूर्ति शृंखला में हैंड सैनिटाइजर की बोतलों का मुफ्त वितरण करेगी।

एक संयुक्त बयान में, क्षेत्र के लिए आपूर्ति श्रृंखला के उपाध्यक्ष उमर नवारो और निविया इंडिया के प्रबंध निदेशक नील जॉर्ज ने शराब बनाने के लिए त्वरित मंजूरी और आवश्यक उत्पाद लाइसेंस के लिए अहमदाबाद में खाद्य और औषधि प्राधिकरण और राज्य निषेध विभाग को धन्यवाद दिया।

आईटी वेंडरों पर काम घटाने का दबाव

देवाशिष महापात्र
बेंगलूरु, 3 अप्रैल

आगे की राह चुनौतीपूर्ण रहने के आसार

- कारोबार थमने के कारण यात्रा एवं आतिथ्य सेवा क्षेत्र की कंपनियां सपोर्ट घटाने के लिए आईटी वेंडरों से संपर्क कर रही हैं
- आगामी तिमाहियों में इससे कीमत को लेकर नए सिरे से करनी पड़ सकती है बातचीत
- जनवरी और फरवरी में हस्ताक्षरित बहुवर्षीय अनुबंधों के तहत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में ग्राहकों की सुस्ती
- कीमत में किसी भी तरह की कमी से आईटी कंपनियों के प्रमुख राजस्व को लगेगा झटका

अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की तमाम कंपनियों ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर फिलहाल अपना कारोबार रोक दिया है अथवा उसे काफी घटा दिया है। अब वे अपने भारतीय आईटी सेवा वेंडरों पर सपोर्ट एवं रखरखाव संबंधी कार्यों को घटाने के लिए दबाव बना रही हैं।

इस मामले से अवगत लोगों ने कहा कि इसे कीमत पर नए सिरे से बातचीत का पूर्व संकेत माना जाना चाहिए क्योंकि आईटी कंपनियों को आगामी तिमाहियों में ग्राहकों के साथ मूल्य निर्धारण पर नए सिरे से बातचीत करनी पड़ सकती है।

एक मझोली आईटी सेवा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हालांकि अभी फोर्स मैज्योर क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए अनुबंधों को रद्द नहीं किया गया है लेकिन तमाम ग्राहक आईटी सपोर्ट का स्तर घटाने के लिए कहने लगे हैं। ऐसा विशेष तौर पर यात्रा एवं आतिथ्य सेवा, तेल एवं गैस और विनिर्माण आदि बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में दिख रहा है।' उन्होंने कहा कि इससे कीमत के मुद्दे पर नए सिरे से बातचीत करने का अवसर पैदा होता है।

भारतीय आईटी कंपनियों के राजस्व में डिजिटल कारोबार से प्राप्त राजस्व की हिस्सेदारी बढ़ी है लेकिन ऐप्लिकेशन एवं रखरखाव संबंधी कार्य जैसे प्रमुख पारंपरिक कारोबार का राजस्व में योगदान अभी भी करीब 60 फीसदी है। यदि आईटी सपोर्ट कारोबार में कमी आई तो प्रमुख कारोबार से प्राप्त राजस्व में निश्चित तौर पर गिरावट आएगी। इसके अलावा कई परियोजनाओं के लिए बिलिंग वहां तैनात इंजीनियरों की संख्या के आधार पर की गई है। ऐसे में सपोर्ट कर्मचारियों में कमी के कारण आगामी दिनों में राजस्व में भी कमी आ सकती है।

आईटी क्षेत्र पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों के अनुसार, आतिथ्य सेवा, विनिर्माण और तेल एवं गैस जैसे क्षेत्रों के ग्राहक अपने आईटी खर्च को फिलहाल टाल सकते हैं। इससे आईटी कंपनियों के निर्यात राजस्व को करीब 10 से 12 फीसदी का झटका लग सकता है जो कुल मिलाकर करीब 15 अरब डॉलर हो सकता है।

कई देशों द्वारा यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ऐसे में कई विमानन कंपनियों ने अपने निवेशकों को बजट में कटौती के बारे में सूचित किया है। अमेरिकी विमानन कंपनी डेल्टा एयरलाइंस ने सार्वजनिक तौर पर अपने खर्च में कटौती करने की घोषणा की है। इसी प्रकार यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, जेटब्लू और साउथवेस्ट एयरलाइंस ने भी ऐसा संकेत दिया है। हॉन्ग कॉन्ग की विमानन कंपनी कैथी पैसिफिक ने कहा है कि कारोनावायरस महामारी के कारण 2020 की पहली छमाही में उसे घाटा हो सकता है। इसके अलावा तमाम विमानन कंपनियों और क्रूज कंपनियों ने 2020 में अपने आईटी खर्च में कटौती करने की घोषणा की है। इन कंपनियों में टोटाल एसए, बीपी, एक्जॉन मोबिल, रॉयल डच शेल और शेवरॉन कॉरपोरेशन आदि शामिल हैं।

एक आईटी आउटसोर्सिंग सलाहकार ने कहा, 'जनवरी और फरवरी में कई बहुवर्षीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए थे। उस लिहाज से संभावित सौदों की संख्या काफी अच्छी है। लेकिन मौजूदा संकट के कारण इन सौदों को आगे बढ़ाने में समय लगेगा।'

ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय आईटी कंपनियों के डॉलर राजस्व में वित्त वर्ष 2021 में 3 फीसदी की गिरावट दिख सकती है। फर्म ने एक नोट में कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल मिलाकर उद्योग की वृद्धि दर करीब 4 फीसदी रहेगी।

कोविड : एफआईआई की बिकवाली से लिक्विड फंडों पर बड़ी चोट

बॉन्ड प्रतिफल बढ़ने से निवेश निकासी का दबाव, आरबीआई के एलटीआरओ से राहत की उम्मीद

जयदीप घोष
नई दिल्ली, 3 अप्रैल

म्युचुअल फंड उद्योग की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों पर मार्च में बड़ी चोट पड़ी, जो मुख्य रूप से डेट फंडों और आर्बिट्राज फंडों से बड़ी निकासी के कारण हुआ। आंकड़ों का हवाला देते हुए सूत्रों ने कहा कि म्युचुअल फंडों से कुल निकासी 29 मार्च तक 2.35 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई। उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा कि अल्पावधि वाले फंडों से शुद्ध निकासी पहले ही 1 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच चुकी थी। इसके अलावा माह के आखिरी दिनों में बिकवाली का कुछ और दबाव देखने को मिला।

डेट फंड, खास तौर से लिक्विड फंडों को भी बॉन्ड के प्रतिफल में इजाफे से झटका लगा। उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा कि एक ही समय में कई चीजें हुईं – अल्पावधि वाले बॉन्ड बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आक्रामक बिकवाली, सक्रियता से कारोबार में कई ब्रोकरों की अक्षमता, अग्रिम कर के लिए कंपनियों की तरफ से बिकवाली और भारी उम्मीद कि रिजर्व बैंक दरों में कटौती करेगा और 20 मार्च को विशेष खिड़की खोलेगा।

हालांकि स्थिति ज्यादा खराब हो गई क्योंकि आरबीआई ने उस तारीख को इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया। लिक्विड फंडों का प्रतिफल 150-170 आधार अंक चढ़ गया और बॉन्ड की कीमतें कम हो गईं, जिससे लिक्विड फंडों का रिटर्न नकारात्मक हो गया। 16 लाख करोड़ रुपये के लिक्विड फंड एयूएम में 90 फीसदी से ज्यादा भागीदारी कंपनियों की है और वह निवेश निकासी के लिए दौड़ पड़ी। एक फंड हाउस के सीईओ ने कहा, इसके अतिरिक्त चिंता इस बात की है कि कोविड-19 का संकट वित्त को झटका दे रहा है, लिहाजा लिक्विड फंडों पर बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है। हमें लगता है कि इस संकट के कारण 70,000 से 80,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निकासी हुई, जो कई सालों की सबसे खराब स्थिति है।

सामान्य तौर पर साल के आखिर में लिक्विड फंडों से शुद्ध निकासी होती है क्योंकि कंपनियां अग्रिम कर चुकाने के लिए रकम निकालती हैं। हालांकि वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेंद्र कुमार जैसे उदद्योग के विशेषज्ञ बताते हैं कि इस साल अग्रिम कर चुकाने का बहुत ज्यादा दबाव नहीं था क्योंकि सरकार ने पिछले साल सितंबर में कर में छूट दी थी।

भारी निकासी के कारण फंड मैनेजर निवेश निकासी का दबाव पूरा करने के लिए और नकदी जुटाने के लिए बाध्य हुए। एक अग्रणी सीईओ ने कहा, कई हफ्ते काफी मुश्किल भरे रहे क्योंकि हमें निवेशकों को रकम न निकालने के लिए समझाना पड़ा या इस दबाव को पूरा करने के लिए लगातार रकम जुटानी पड़ी।

म्युचुअल फंड उद्योग ने अपनी उद्योग निका एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया के जरिये विशेष खिड़की के लिए आरबीआई से संपर्क किया, जैसा कि साल 2009 और साल 2013 में हुआ था। लेकिन केंद्रीय बैंक ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय आरबीआई ने 27 मार्च को एक लाख करोड़ रुपये के एलटीआरओ यानी लॉन्ग टर्म रीपो ऑपरेशन का ऐलान किया। चूंकि आरबीआई 4.4 फीसदी पर उधार दे रहा है और मौजूदा वाणिज्यिक प्रतिभूतियां व सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 6 फीसदी पर हो रहा है, ऐसे में बैंकों को इनमें निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया। यह म्युचुअल फंड उद्योग का दबाव घटाएगा, जिन्हें निवेश निकासी का दबाव पूरा करने के लिए रकम चाहिए।

बिड़ला सन लाइफ म्युचुअल फंड के सीईओ ए बालासुब्रमण्यन ने कहा, आरबीआई की नीति की घोषणा के बाद फिक्स्ड इनकम वाली प्रतिभूतियों का नकारात्मक रिटर्न चिंता का विषय शायद नहीं रहेगा, खास तौर से लिक्विड व अल्पावधि वाली योनजाओं में। अल्पावधि वाली दरें अभी निचले स्तर पर रहेगी क्योंकि नकदी ज्यादा है और बैंकों ने भी जमा दरों में कटौती की है।

फर्स्टरैंड बैंक के ट्रेजरर के हरिहर इससे सहमत हैं। उन्होंने कहा, मंहगाई उच्चस्तर पर है और व्यवस्था में करीब 4 लाख करोड़ रुपये की नकदी है। यह दरों को तब तक नियंत्रण में रखेगा जब तक कि सरकार उधारी कार्यक्रम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करती।

माह के दौरान हालांकि इक्विटी प्रवाह सकारात्मक रहा, लेकिन बाजार में मचे हाहाकार ने कुल एयूएम पर करीब 25 फीसदी की चपत लगाई। उद्योग के प्रतिभागियो ने कहा कि इक्विटी का एयूएम करीब 8 लाख करोड़ रुपये है, जो पहले 11.45 लाख करोड़ रुपये था।

कोटक म्युचुअल फंड के प्रबंध निदेशक निलेश शाह ने कहा, लेकिन एक श्रेणी आर्बिट्रेज फंडों को गंभीर झटका लगा। यह घबराहट महीने की तीसरे महीने में देखने को मिली जब आर्बिट्रेज फंडों से भारी निवेश निकासी हुई क्योंकि बाजार में कोई मौका नहीं था।

लिक्विड फंड

- म्युचुअल फंडों से कुल निकासी 29 मार्च तक 2.35 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई
- खास तौर से लिक्विड फंडों को बॉन्ड के प्रतिफल में इजाफे से झटका लगा
- सामान्य तौर पर साल के आखिर में लिक्विड फंडों से शुद्ध निकासी होती है क्योंकि कंपनियां अग्रिम कर चुकाने के लिए रकम निकालती हैं

केंद्र और राज्यों की उधारी योजना से बॉन्ड बाजार चिंतित

अनूप रॉय
मुंबई, 3 अप्रैल

शुक्रवार को बॉन्ड प्रतिफल बढ़ गया, क्योंकि बॉन्ड डीलरों ने भारी साप्ताहिक उधारी के आंकड़ों को लेकर अपनी निराशा जताई, वहीं आरबीआई के साथ निजी नियोजन को लेकर भी कोई खबर नहीं आई है।

सरकार और आरबीआई ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए पांच विशेष प्रतिभूतियां निर्धारित की हैं, लेकिन इनके आने और भारतीय ऋण पत्रों में दिलचस्पी बढ़ने में समय लगेगा। वित्त वर्ष 2019-20 में एफपीआई ने 48,710 करोड़ रुपये के डेट की बिक्री की थी, जबकि अकेले मार्च में उन्होंने लगभग 62,000 करोड़ रुपये की बिकवाली की।

> वित्त वर्ष 2019-20 में एफपीआई ने 48,710 करोड़ रुपये के डेट की बिक्री की थी, जबकि मार्च में उन्होंने लगभग 62,000 करोड़ रुपये की बिकवाली की

10 वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल 6.305 प्रतिशत पर बंद हुआ, जो पूर्ववर्ती बंद स्तर 6.138 के मुकाबले ज्यादा है। रुपया अपने वित्त वर्ष 2019-20 के 75.6 डॉलर के बंद स्तर के मुकाबले 76.13 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद बाजार दो दिन तक बंद थे।

हालात जिस वजह से जटिल हुए हैं, वह यह है कि अब राज्यों ने मौजूदा बाजार हालात में अपनी उधारी के साथ उधारी को लेकर रणनीति में बदलाव किया है। मौजूदा कैलेंडर वर्ष में, जहां केंद्र पहली छमाही में 4.88 लाख करोड़ रुपये की उधारी लेगा, वहीं राज्य पहली तिमाही में 1.27 लाख करोड़ रुपये की उधारी लेंगे। केयर रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में राज्यों ने 81,523 करोड़ रुपये की उधारी ली थी।

केनरा रोबेको ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी में फिक्स्ड इनकम के प्रमुख अवनीश जैन ने कहा, 'चालू वित्त वर्ष में राज्य ऋणों की पहली नीलामी में जुटाई जाने वाली रकम 36,000 करोड़ रुपये है जो सर्वाधिक है।'

जैन ने कहा, 'फरवरी से जी-सेक की आपूर्ति नहीं हुई है, जिसकी वजह से बाजार में स्थिरता आई है। हालांकि अब केंद्र और राज्य दोनों की उधारी शुरू होने से मांग अब आपूर्ति के अनुरूप नहीं रह सकती है।'

बॉन्ड डीलरों का कहना है कि ज्यादा आपूर्ति ऐसे समय में चिंता का मुख्य कारण है जब कोरोनावायरस के प्रभाव की वजह से बिक्री में कमी आई है और किसी को यह पता नहीं है कि अनिश्चितता कम समाप्त होगी। एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक में 'ऐसेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट' (एएलएम) के प्रमुख देवेंद्र दास ने कहा, 'बाजार कुछ ओएमओ (ओपन मार्केट ऑपरेशन) की भी उम्मीद कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे समय में बॉन्ड आपूर्ति ज्यादा बनी हुई है जब एफपीआई रकम निकाल रहे हैं। मौजूदा समय में मांग आपूर्ति के बीच असमानता स्पष्ट है।' भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष अतिरिक्त समर्थता को अनिवार्यता के तौर पर देख रहे हैं। घोष ने कहा है, 'जीडीपी में कम से कम 4 प्रतिशत अंतर को देखते हुए हमें उम्मीद है कि केंद्र और राज्य वित्त वर्ष 2021 में लगभग 20 लाख करोड़ रुपये की उधारी पर ध्यान दे सकते हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि आरबीआई घाटे का मुद्रीकरण करे, बाजार क्षमता पर दबाव को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा क्लॉज का इस्तेमाल करे।'

बॉन्ड व मुद्रा बाजार 2 बजे बंद करेगा भारतीय रिजर्व बैंक

अनूप रॉय
मुंबई, 3 अप्रैल

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि बॉन्ड व मुद्रा बाजार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बजाय 10 बजे से 2 बजे तक परिचालन में रहेगा और नई समयसारणी 7 से 17 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। आरबीआई ने कहा कि कोरोनावायरस से जुड़ी अव्यवस्था के कारण यह फैसला लिया गया है।

बाजारों का सामान्य समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे का है, जो प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग पर निर्भर है। उदाहरण के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में रीपो सुबह 9 बजे से 2.30 बजे तक उपलब्ध है, वहीं कॉरपोरेट बॉन्ड में रीपो शाम 6 बजे बंद होता है। अब सबकुछ 2 बजे बंद हो जाएगा। अपनी वेबसाइट पर आरबीआई ने कहा है, कोविड-19 के प्रसार ने अप्रत्याशित हालात पैदा कर दिए हैं और लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य बना दिया है जबकि लोगों की आवाजाही पर पाबंदी और गैर-जरूरी गतिविधियों पर रोक है। इसके अलावा घर से काम करने की व्यवस्था और कारोबारी निरंतरता की योजना बनानी पड़ी है।

केंद्रीय बैंक ने कहा है, इसके परिणामस्वरूप फैली अव्यवस्था का वित्तीय बाजारों के कामकाज पर विपरीत असर पड़ा है। कर्मचारी और आईटी संसाधन काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जो परिचालन और लॉजिस्टिक्स का जोखिम पैदा कर रहे हैं। गतिविधियां कम होने से बाजार की तरलता पर असर पड़ रहा है और वित्तीय कीमतों में उतारचढ़ाव में इजाफा हो रहा है। इसलिए इन जोखिमों को कम करने और बाजार के प्रतिभागियों की तरफ से कम संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त नियंत्रण व निगरानी के अलावा कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की खातिर केंद्रीय बैंक ने बाजार के कामकाज का समय घटाया है। बाजार के प्रतिभागियों ने इस कदम का स्वागत किया है। ज्यादातर लोग हालांकि घर से काम कर रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ कर्मियों को ट्रेडिंग फ्लोर पर आना पड़ रहा है।

एमके ग्लोबल फाइनैंशियल के शोध प्रमुख (करेंसी) राहुल गुप्ता ने कहा, ओवर द काउंटर समय में कमी सटोरियों को निराश करेगा और वॉल्यूम में कमी लाएगा। वॉल्यूम में कमी से बाजार की तरलता पर असर पड़ेगा और उतारचढ़ाव में संभावित बढ़ोतरी से रुपये पर जोखिम होगा। आरबीआई ने आश्वस्त किया है कि आरटीजीएस, नेफ्ट, ई-कुबेर (बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) और अन्य खुदरा भुगतान की व्यवस्था समेत सामान्य बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता मौजूदा समय के मुताबिक जारी रहेगी।

डाउनग्रेड के लिए इंडसइंड बैंक की रेटिंग समीक्षा के दायरे में

मूडीज ने आईसीआईसीआई बैंक, ऐक्सिस बैंक का परिदृश्य संशोधित कर नकारात्मक किया

अभिजित लेले
मुंबई, 3 अप्रैल

रेटिंग एजेंसी मूडीज ने डाउनग्रेड करने के लिए निजी क्षेत्र के बैंक इंडसइंड बैंक की देसी व विदेशी इश्यूअर रेटिंग बीएएए3/पी-3 को समीक्षा के दायरे में ला दिया है। इसके अलावा एजेंसी ने बैंक का बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट (बीसीए) बीए1 और समायोजित बीसी को डाउनग्रेडिंग के लिए समीक्षा के दायरे में कर दिया है। भारतीय बैंकिंग सिस्टम का परिदृश्य डाउनग्रेड कर स्थिर से नकारात्मक किए जाने की पृष्ठभूमि में रेटिंग की यह कवायद देख ने को मिली है क्योंकि कोविड-19 महामारी के प्रसार का विपरीत असर और डिफॉल्ट में इजाफा बैंकिंग इकाइयों के जोखिम में बढ़ोतरी कर रहा है। इसके अलावा आईसीआईसीआई और ऐक्सिस बैंक का परिदृश्य स्थिर से नकारात्मक कर दिया गया है और आईडीबीआई का परिदृश्य सकारात्मक से स्थिर किया गया है। मूडीज ने एक बयान में यह जानकारी दी।

रेटिंग एजेंसी ने आईसीआईसीआई बैंक और ऐक्सिस बैंक की डिपॉजिट रेटिंग बीएए3 बनाए रखी है और एक अन्य निजी बैंक आईडीबीआई बैंक की रेटिंग बीए2 रखी है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक और ऐक्सिस बैंक का बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट (बीसीए) और समायोजित बीसीए बीए1 रखा गया है। आईडीबीआई का बीसीए व समायोजित बीसीए बी2 रखा गया है।

मूडीज ने गुरुवार को कहा था कि कोरनावायरस महामारी के प्रसार के कारण आर्थिक गतिविधियों पर पड़े व्यवधान से देश की आर्थिक रफ्तार की सुस्ती में और इजाफा होगा। बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता पर असर होगा और इस वजह से लाभ व पूंजी पर दबाव पड़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की फंडिंग व तरलता स्थिर रहेगी क्योंकि लोगों का भरोसा इनके प्रति मजबूत बना रहेगा, जिसकी वजह सरकारी समर्थन है। येस बैंक के डिफॉल्ट के बाद भी इस भरोसे पर असर नहीं पड़ा था।

मूडीज ने कहा, निजी क्षेत्र के एक बैंक की तरफ से डिफॉल्ट के बाद जोखिम के प्रति बढ़ती अरुचि छोटे निजी बैंकों पर फंडिंग व नकदी का दबाव बढ़ाएगा। बड़े निजी बैंकों की फंडिंग व नकदी स्थिर रहेगी क्योंकि उनके पास अच्छी तरह से स्थापित फ्रैंचाइजी और जमाकर्ताओं का मजबूत आधार है। वैश्विक आर्थिक हालात खराब होने और कोरोनावायरस के प्रसार पर लगाम कसने के लिए भारत सरकार की तरक से 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान देसी मांग और निजी निवेश पर असर डालेगा।

कई शेयरों में बढ़ी एफपीआई निवेश की सीमा

बीएस संवाददाता
मुंबई, 3 अप्रैल

विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए कई कंपनियों में निवेश की सीमा बढ़ी है। एक अप्रैल से प्रभावी एफपीआई निवेश की सीमा को क्षेत्रीय सीमा मानने के सरकार के फैसले के बाद यह हुआ है। शुक्रवार को डिपॉजिटरी फर्मों एनएसडीएल और सीडीएसएल ने उन कंपनियों की सूची जारी की, जहां एफपीआई के लिए अतिरिक्त शेयर उपलब्ध हैं।

बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि सीमा बढ़ाए जाने से अरबों रुपये का विदेशी निवेश आकर्षित हो सकता है, लेकिन यह शायद तत्काल नहीं देखने को मिलेगा।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के खुदरा शोध प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, संबंधित क्षेत्रीय सीमा तक एफपीआई निवेश की सीमा बढ़ाया जाना स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन एफपीआई की मौजूदा अवधारणा बहुत अनुकूल नहीं है कि इस रियायत क आधार पर निवेश आकर्षित किया जा सके।

बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक और लार्सन ऐंड टुब्रो के शेयर में अचानक आई उछाल एनएसडीएल और सीडीएसएल की तरफ से सूची जारी करने की वजह से है।

एलकेपी सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख एस रंगनाथन ने कहा, कोटक बैंक और एलऐंडटी जैसे कुछ दिग्गजों ने एमएससीआई में संभावित बदलाव के कारण हुए कुछ नुकसान की भरपाई कर ली। उन्होंने कहा कि इंडेक्स प्रदाता अब देसी शेयरों का भारांक बढ़ाने में सक्षम है।

मंगलवार को एमएससीआई ने अनिश्चितता का हवाला देते हुए अपना फैसला टाल दिया था। एमएससीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा था, एमएससीआई इंडेक्सों में किसी तरह के बदलाव से पहले वह इन परिवर्तनों के व्यावहारिक क्रियान्वयन और भारतीय प्रतिभूतियों के लिए लागू नई क्षेत्रीय सीमा के प्रकाशन का इंतजार करेगा। इंडेक्स प्रदाता की तिमाही इंडेक्स समीक्षा अगस्त में होगी।

कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही में निवेश बैंकिंग शुल्क 34 फीसदी घटा

कैलेंडर वर्ष 2020 की पहली तिमाही में निवेश बैंकिंग शुल्क सालाना आधार पर 34 फीसदी घटकर 22.2 करोड़ डॉलर रह गया। इसमें विलय व अधिग्रहण, इक्विटी बाजार पूंजी (ईसीएम) और डेट कैपिटल मार्केट (डीसीएम) जैसी गतिविधियों अर्जित शुल्क शामिल है। एक ओर जहां ईसीएम गतिविधियों से शुल्क 33 फीसदी बढ़ा, वहीं विलय व अधिग्रहण और डीसीएम गतिविधियों से शुल्क में क्रमशः 66 फीसदी और 23 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। यह जानकारी रेफिनिटिव की तरफ से प्रकाशित रिपोर्ट से मिली। ईसीएम गतिविधियों को भारती एयरटेल की तरफ से 2 अरब डॉलर जुटाए जाने और एसबीआई कार्ड्स की तरफ से 1.4 अरब डॉलर जुटाए जाने से मजबूती मिली। इसके अलावा पीरामल एंटरप्राइजेज के 51 करोड़ डॉलर के राइट्स इश्यू और एवेन्यू सुपरमार्ट्स की तरफ से 57.5 करोड़ डॉलर की इक्विटी शेयर बिक्री से भी उसे सहारा मिला। निवेश बैंकिंग शुल्क की सूची में देसी बैंकों का वर्चस्व रहा। ऐक्सिस बैंक को शुल्क के तौर पर सबसे ज्यादा रकम मिली, जिसके बाद आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई को क्रमशः 1.8-1.8 करोड़ डॉलर मिले। *समी मोडक*

देसी बैंकों का दबदबा

पहली तिमाही में निवेश बैंकिंग शुल्क की सूची में देसी बैंक अव्वल

जनवरी-मार्च 2020

बैंक	शुल्क करोड़ डॉलर	बदलाव फीसदी	बाजार हिस्सा फीसदी	सौदे की संख्या
ऐक्सिस बैंक	1.85	-39.9	8.3	53
आईसीआईसीआई बैंक	1.8	3.8	8.1	56
एसबीआई	1.77	-56	8.0	24
जेपी मॉर्गन	1.28	-14.9	5.8	13
ईवाई	0.97	143.9	4.4	7
सिटी	0.93	8.3	4.2	10
बोफा	0.90	17.4	4.0	10
बार्कलेज	0.84	-6.6	3.8	13
एंबिट	0.75	1038.9	3.4	2
मॉर्गन स्टैनली	0.72	-29.7	3.3	3

इक्विटी के जरिये रकम जुटाने के मामले बढ़े, 62 फीसदी की उछाल

33,556 करोड़ रुपये के आईपीओ पर महामारी का साया

जश कृपलानी
मुंबई, 3 अप्रैल

वित्त वर्ष 2019-20 में इक्विटी के जरिए 62 फीसदी ज्यादा रकम जुटाई गई। इस दौरान आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये 20,350 करोड़ रुपये जुटाए गए जबकि पहले से सूचीबद्ध कंपनियों ने क्यूआईपी के जरिये 51,216 करोड़ रुपये जुटाए। बुधवार को प्राइम डेटाबेस ने प्राथमिक बाजार में हुई वित्त वर्ष 2020 की गतिविधियों के आंकड़े जारी किए, साथ ही यह भी बताया कि कोरोनावायरस महामारी के प्रसार के बीच आईपीओ की गतिविधियों में भारी सुस्ती देखने को मिल सकती है।

करीब 26 कंपनियों को आईपीओ लाने की मंजूरी बाजार नियामक सेबी से मिल गई है और ये कंपनियां 26,056 करोड़ रुपये जुटाएंगी। इसके अलावा छह कंपनियों को अभी सेबी की मंजूरी नहीं मिली है, जिनकी योजना 7,500 करोड़ रुपये जुटाने की है।

प्राइम डेटाबेस समूह के प्रबंध निदेशक प्रणव हल्दिया ने कहा, जब तक कोरोनावायरस महामारी की अनिश्चितता खत्म नहीं हो जाती, तब तक इनमें से कोई आईपीओ शायद ही बाजार में उतारा जाएगा।

सूचीबद्ध कंपनियों ने क्यूआईपी के जरिये इस दौरान 51,216 करोड़ रुपये जुटाए

वित्त वर्ष 2020 में विभिन्न जरिये से 91,670 करोड़ रुपये की इक्विटी जुटाई गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 56,485 करोड़ रुपये रही थी। वित्त वर्ष के दौरान संस्थागत और खुदरा निवेशकों के बीच आईपीओ की खासी दिलचस्पी देखी गई। हल्दिया ने कहा, पिछले वर्षों के उलट 13 में से 7 आईपीओ अभी भी इश्यू प्राइस से 8 से 207 फीसदी नीचे कारोबार कर रहे हैं, जो 31 मार्च 2020 के बंध भाव के आधार पर है।

क्यूआईपी की गतिविधियां करीब पांच गुनी रही, जिसमें ऐक्सिस बैंक (12,500 करोड़ रुपये), बजाज फाइनैंस (8,500 करोड़ रुपये) का अहम योगदान रहा। राइट्स इश्यू के जरिये जुटाई गई रकम बढ़कर 55,998 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

बड़ा इश्यू कर्ज का सामना कर रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया (25,000 करोड़ रुपये) और भारती एयरटेल (24,939 करोड़ रुपये) का रहा और उन्होंने इसमें अहम योगदान किया। बॉन्ड के जरिये रकम जुटाने का मामला वित्त वर्ष 2020 में 59 फीसदी घटा। करीब 35 इश्यू के जरिये 14,996 करोड़ रुपये जुटाए गए जबकि इससे पिछले साल 20 इश्यू के जरिये 36,788 करोड़ रुपये जुटाए गए थे।

एमसीएक्स पर कच्चे तेल ने लगाई छलांग

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 3 अप्रैल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर आज दोपहर बाद के कारोबार में कच्चे तेल के दामों में 26 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई जिसका अहम कारण रूस तथा सऊदी अरब के बीच तेल उत्पादन कटौती पर समझौते के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में सकारात्कम रूख रहा। दोनों देश अगले सप्ताह बैठक करेंगे।

अप्रैल में डिलिवरी के लिए बेंचमार्क कच्चे तेल के वायदा कारोबार में शुक्रवार को 26.03 प्रतिशत की तेजी आई और इसकी कीमतें 2,043 रुपये प्रति बैरल तक पहुंच गईं। इसी तरह की तेजी दूसरे बाजारों में भी देखी गई और गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा ट्वीट किए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 30 प्रतिशत तक की तेजी देखी गई। ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने उत्पादन कटौती के लिए सऊदी अरब तथा रूस – दोनों देशों से बात की है। कच्चे तेल के मामले में धनी दोनों देशों के बीच लड़ाई से कच्चे तेल की कीमतों में पिछले तीन महीनों के दौरान दो-तिहाई गिरावट देखी गई और यह वर्ष 2016 के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गईं।

कच्चे तेल के साथ ही सराफा तथा धातु की कीमतों में भी तेजी देखी गई। जून में डिलिवरी के लिए सोने की कीमतें 1.11 प्रतिशत चढ़कर 43,722 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गईं, वहीं मई डिलिवरी के लिए चांदी का वायदा भाव 3.4 प्रतिशत तेजी के साथ 41,227 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। आने वाले महीने में डिलिवरी से जुड़े तांबा, जस्ता और दूसरी धातुओं के वायदा में भी करीब एक प्रतिशत की तेजी देखी गई। शुक्रवार को दोपहर बाद के कारोबार में एमसीएक्स आईकॉमडेक्स में कुल 3.9 फीसदी की उछाल आई।

कॉमट्रेंड्ज के निदेशक ज्ञानशेखर त्यागराजन ने कहा, 'सऊदी अरब और रूस के बीच उत्पादन कटौती की उम्मीद के बीच शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई तथा मूल धातुओं की कीमतों में उछाल आई। साथ ही सोने में कुछ निवेशकों की रुचि बढ़ी है क्योंकि वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने आर्थिक अनिश्चितता के खिलाफ सुरक्षित निवेश के रूप में अपनी मौजूदा होल्डिंग में सोने को जोड़ना जारी रखा। चांदी तथा दूसरी धातुएं भी मामूली तौर पर चढ़ी हैं।'

आईएएस अधिकारियों की कोविड पर खर्च बढ़ाने व देशबंदी की अवधि बढ़ाने की अपील

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 3 अप्रैल

प्रधानमंत्री कार्यालय के एक फीडबैक सर्वे में आईएएस अधिकारियों व जिलाधिकारियों के एक समूह ने कहा है कि देश पर वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के संकट को देखते हुए सरकार को गरीबों व हाशिये पर खड़े समाज के लिए स्वास्थ्य सेवाओं व जरूरी जिंसों पर राजकोषीय व्यय बढ़ाकर जीडीपी का करीब 2 प्रतिशत करने की जरूरत है।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की ओर से कोविड-19 की राष्ट्रीय तैयारियों को लेकर 410 नौकरशाहों के बीच सर्वे कराया गया, जिससे किसभी राज्यों की तैयारियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके और आगे का खाका तैयार करने में खामियों को चिह्नित किया जा सके।

सरकार का खर्च बढ़ाकर 5 से 10 लाख करोड़ रुपये की सिफारिश करने के अलावा अधिकारियों ने आपात कदमों के सुझाव देते हुए जरूरी होने पर देशबंदी की अवधि बढ़ाने की बात कही है। इसमें कहा गया है, '21 दिन की देशबंदी का इस्तेमाल ज्यादा पॉजिटिव मामलों को चिह्नित करने में किया जाना चाहिए और उनके संपर्क में आए सभी लोगों को एकांतवास में भेजा जाना चाहिए।'

अधिकारियों ने कहा है कि देशबंदी तब तक जारी रखी जाए, जब तक कोविड-19 नियंत्रण में नहीं आ जाता है। उन्होंने कहा है कि देशबंदी का पालन न करने वाले लोगों, खासकर जहां 50 लोगों से ज्यादा एकत्र होते हैं, के साथ सख्ती से पेश आने की जरूरत है।

शुक्रवार को प्रयागराज में बने कोविड-19 क्वारंटीन केंद्र पर तापमान की जांच करता स्वास्थ्यकर्मी। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुए धार्मिक आयोजन में शामिल हुए लोगों को एकांतवास में रखा गया है -*पीटीआई*

अफसरशाही ने कहा

- 21 दिन की देशबंदी का इस्तेमाल ज्यादा पॉजिटिव मामलों को चिह्नित करने में किया जाना चाहिए और उनके संपर्क में आए सभी लोगों को एकांतवास में भेजा जाना
- गरीबों व हाशिये पर खड़े समाज के स्वास्थ्य सेवाओं व जरूरी जिंसों पर राजकोषीय व्यय बढ़ाकर जीडीपी का करीब 2 प्रतिशत करने की जरूरत

उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि कालाबाजारी को रोकने के लिए मूल्य तय किया जाए और जरूरी सामान के मूल्य की जांच के लिए अनिवार्य नियमित जांच की जाए।

अन्य सुझावों में जरूरी सामान की आवाजाही के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच तालमेल, विस्थापित श्रमिकों और दैनिक मजदूरी करने वालों को आर्थिक मदद दिया जाना शामिल है।

प्रतिक्रिया देने वालों ने कहा है कि सरकार को जांच किट के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, ज्यादा जांच केंद्र स्थापित करने और सभी जिला और क्षेत्रीय अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने व आइसोलेशन वार्ड बनाने का काम करना चाहिए, जिससे अनावश्यक देरी को रोका जा सके।

इस सर्वे में राज्य विशेष पर केंद्रित चुनौतियों की पहचान की गई है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और नगालैंड में व्यक्तिगत बचाव उपकरण (पीपीई) और मेडिकल सुविधा की अपर्याप्तता और बुनियादी मेडिकल उपकरणों जैसे मास्क और सैनिटाजर की कमी की जानकारी मिली है।

हरियाणा में मरीजों को चिह्नित करना व परीक्षण करना और विस्थापन को बड़ी चुनौती बताया गया है। साथ ही पीपीई और वेंटिलेटरों की कमी को भी अहम बताया गया है। झारखंड के दुमका जिले के बारे में कहा गया है कि यहां एनेस्थेटिक सुविधा नहीं है और ऐसे में वेंटिलेटर नहीं चलाए जा सकते हैं। वहीं असम को उचित तरीके से देशबंदी को लागू करने में संकट हो रहा है।

प्रतिक्रिया देने वाले 75 प्रतिशत लोगों ने कहा कि लोग इस वैश्विक महामारी को लेकर सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। इसमें शामिल 69 प्रतिशत लोगों का कहना है कि लोग देशबंदी को शांतिपूर्ण तरीके से मान रहे हैं, जबकि 31 प्रतिशत ने कहा कि लोग सावधान व घबराए हुए हैं।

वैश्विक महामारी कोविड-19 से अब तक 5 लाख लोगों के प्रभावित होने की पुष्टि हुई है और 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

चुनिंदा शहरों में एमेजॉन पैंट्री की सेवाएं शुरू

समरीन अहमद
बेंगलूरु, 3 अप्रैल

ई-कॉमर्स कंपनी की रोजमर्रा की जरूरतों वाले सामान का स्टोर एमेजॉन पैंट्री अब प्राइम सदस्यों के लिए ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए तैयार है और यह कुछ शहरों में ऑर्डर भी लेने लगा है। पिछले हफ्ते इसकी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गईं थीं।

अब यह बेंगलूरु, हैदराबाद और पुणे जैसे चुनिंदा पिन कोड के लिए खुला है। यह रियायती दरों पर खाद्य वस्तुएं, पेय पदार्थ, घरेलू सामानों की आपूर्ति करने के साथ ही स्वास्थ्य और सौंदर्य उत्पादों की आपूर्ति करता है। कंपनी ने कहा, 'हम मौजूदा ऑर्डर की डिलिवरी को प्राथमिकता दे रहे हैं। नए ऑर्डर की डिलिवरी में 7-10 दिन लग सकते हैं।' देश में लॉकडाउन की घोषणा की वजह से अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से रोकने से पहले एमेजॉन पैंट्री 100 से अधिक शहरों में जरूरी सामानों की आपूर्ति कर रही थी।

एमेजॉन इंडिया अब जरूरी सामानों के मौजूदा ऑर्डर की डिलिवरी कर रही है जिसकी खरीदारी प्रीपेड भुगतान विकल्प के जरिये की गई थी।

एमेजॉन इंडिया के कंट्री हेड अमित अग्रवाल ने ट्विटर पर कहा, 'हम फिलहाल जरूरी सामानों की आपूर्ति आप तक करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हमें मंजूरी मिले और जिले के अधिकारियों से संपर्क कर कर्फ्यू पास लेने की कोशिश कर रहे हैं।'

कंपनी कोविड-19 के संकट के इस दौर में एलेक्सा को भी इसके लिए तैयार कर रही है।

कंपनी ने अपने आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के दिशानिर्देश के साथ एलेक्सा टीम ने भारत केंद्रित अनुभव के आधार पर ऐसे तरीके तैयार किए हैं जिनकी वजह से आप एलेक्सा का इस्तेमाल कर घर बैठे ही कोविड-19 के लक्षण की जांच कर सकते हैं।' इसके अलावा यह एमेजॉन के ग्राहकों को किंडल ऐप पर मुफ्त पढ़ने के लिए ई-बुक भी मुहैया करा रही है।

मांग के मोर्चे पर फिक्रमंद तेल कंपनियां

हाल के दिनों में कच्चे तेल के दाम में बहुत उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन कंपनियों को इससे निपटने का अनुभव

अमृता पिल्लै
मुंबई, 3 अप्रैल

कच्चे तेल के दाम में उतार चढ़ाव और पेट्रोलियम की अनिश्चित मांग तेल कंपनियों की चिंता बढ़ा रही हैं। ऐसी स्थिति पिछले एक पखवाड़े से है। उत्पादन में कटौती को लेकर हुए समझौते पर बातचीत करने के लिए गुरुवार को सऊदी अरब ने ओपेक प्लस देशों व अन्य उत्पादकों की 'तत्काल बैठक' बुलाई, जिसके बाद कच्चे तेल के दाम में 25 प्रतिशत की कमी आई। शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में एसऐंडपी प्लैट्स ने कहा, 'एनवाईएमईएक्स के फ्रंट मंथ कच्चे तेल का दाम 25.32 डॉलर प्रति बैरल रहा, जो 5.02 डॉलर ज्यादा है।'

अमेरिका के राष्ट्रपति ने गुरुवार को 10 मिलियन बैरल प्रति दिन से लेकर 15 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती करने के लिए समझौते के संकेत दिए हैं। डेलॉयट टच तोमात्सू में पार्टनर देवाशीष मिश्र ने कहा, 'अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट के बाद कल कच्चे तेल के दाम में अचानक तेजी आई, लेकिन तेल के दाम में गिरावट बनी रहेगी जो ओएमसी के लिए बेहतर है।'

उत्पादन में कटौती से कच्चे तेल के दाम में गिरावट रुक सकती है, लेकिन इससे मांग आपूर्ति की गणित स्थिर होने की संभावना नहीं है।

एक घरेलू ब्रोकरेज फर्म में विश्लेषक ने नाम न दिए जाने की इच्छा जताते हुए कहा, 'मांग तेजी से गिर रही है।' तेल विपणन कंपनियों के अधिकारी भी इसी तरह की चिंता जता रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने पहले ही रिफाइनरी उत्पादन में 30 प्रतिशत तक की कमी कर दी है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) ने 20 प्रतिशत कटौती की है। दोनों कंपनियों ने भारतीय बाजार में उत्पाद की मांग में कमी को देखते हुए यह फैसला किया है।

अधिकारियों ने कहा कि अगर देशव्यापी बंदी की तिथि 15 अप्रैल से आगे बढ़ती है तो तेलशोधन संयंत्रों को तेज कटौती करने का फैसला करना पड़ सकता है।

तेल क्षेत्र की चिंता

- भारत में पिछले एक पखवाड़े में पेट्रोलियम की मांग में बहुत तेजी से गिरावट आई है
- इसके कारण कई कंपनियों ने घटा दिया है उत्पादन
- उत्पादन में कटौती से कच्चे तेल के दाम में गिरावट रुक सकती है, इससे मांग आपूर्ति स्थिर नहीं होगी
- हालांकि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि मांग में मौजूदा कमी अस्थाई

एक सरकारी तेल कंपनी के अधिकारी ने कहा, 'तेल कंपनियां कच्चे तेल के दाम में उतार चढ़ाव की स्थिति में काम करने की आदती हैं। एक दिन की तेजी या कमी से हमें कोई चिंता नहीं होती है। अगर कीमतें स्थिर बनी रहती हैं तो हमें भंडारण के नुकसान या फायदे की चिंता नहीं है। कच्चे तेल और उत्पाद के दाम का मिश्रण ज्यादा अहम है। अभी अन्य उत्पादों की तुलना में डीजल से मुनाफा बेहतर है। इसके साथ ही स्थिर उच्च दाम भी कार्यशील पूंजी पर असर डालेगा।'

विश्लेषकों ने पहले ही मार्च तिमाही के लिए भंडार में ज्यादा कमी की बात की है। उपरोक्त उल्लिखित एक विश्लेषक ने कहा, 'भंडार में मौजूदा उतार चढ़ाव का असर जून तिमाही के आंकड़ों में नजर आएगा।' उन्होंने कहा कि ओएमसी ने अब तक विपणन के मामले में उत्पाद के दाम यथावत रखा है, यह कच्चे तेल के दाम में किसी तेजी की स्थिति में बफर का काम कर सकता है।

मांग में गिरावट को देखते हुए समाचारों में कहा गया है कि आईओसी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) जैसी कंपनयों ने पहले ही कुछ आपूर्तिकताओं को फोर्स मेजर जारी कर दिया है। बहरहाल इस कदम से उल्लेखनीय मदद मिलेगी।

उपरोक्त उल्लिखित तेल कंपनी के अधिकारी ने कहा, 'इस तरीके का अपना सकारात्मक आर नकारात्मक असर है। अभी यह व्यापक तौर पर स्थापिक होना बाकी है कि यह भगवान का काम है। इसमें यह समस्या है कि पंचाट की लागत कॉर्गो को रोकने की तुलना में ज्यादा आती है।'

उपरोक्त उल्लिखित विश्लेषक ने कहा, 'कीमतों के मौजूदा उतार चढ़ाव की स्तिति में फोर्स मेजर तभी मददगार होगा, जब जून तिमाही के लिए भंडारण कम हो और अप्रैल में कीमतें ज्यादा होने पर भंडारण में किसी नुकसान से बचा जाए।'

वहीं कुछ अन्य मध्यम से दीर्घावधि के हिसाब से भारतीय तेलशोधकों के मामले में निश्चिंत बने हुए हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस में कॉर्पोरेट फाइनैंस ग्रुप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकास हालन ने कहा, 'हमारा मानना है कि मौजूदा स्थिति ढांचागत होने के बजाय अस्थाई है। मध्यावधि से दीर्घावधि हिसाब से भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग स्थिर रहेगी और अगर तेल की कीमतें कम बनी रहती हैं तो इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। बहरहाल विमान ईंधन की मांग सुधरने में अभी वक्त लग सकता है।'

कोरोना संकट को लेकर घबराए परिधान निर्यातक

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 3 अप्रैल

फैक्टरियां बंद हैं। कामगार जा चुके हैं। वैश्विक मांग घट गई है। ऐसे में चिंतित परिधान निर्यातकों ने चेतावनी दी है कि अगर इस क्षेत्र के लिए जल्द राहत पैकेज की घोषणा नहीं की जाती है तो लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं।

21 दिन की देशबंदी में उद्योगों का पहिया थम गया है। ऐसे में उद्योग को यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े ग्राहकों की ओर से विदेशी ऑर्डर रद्द किए जा रहे हैं। साथ ही श्रमिकों की अचानक आई कमी की वजह से भी यह क्षेत्र थमा है क्योंकि औद्योगिक इलाकों से बड़े पैमाने पर कामगार दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में चले गए हैं।

उद्योग के अनुमान के मुताबिक करीब 70 प्रतिशत परिधान इकाइयां सूक्ष्म, लघु और मझोले क्षेत्र में आती हैं। इस उत्पाद में मजदूरी पर खर्च 25 से 30 प्रतिशत है, जबकि इसके अतिरिक्त कुल मिलाकर घरेलू उद्योगों में वेतन पर 7-8 प्रतिशत खर्च का मानक है।

प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के चेयरमैन ए शक्तिवेल ने कहा कि इस उद्योग में 1.29 करोड़ कामगार लगे हुए हैं और अगर सरकार तत्काल परिधान क्षेत्र के लिए पैकेज की घोषणा नहीं करती है तो यह क्षेत्र धीरे धीरे मर जाएगा। शक्तिवेल ने कहा है, 'परिधान उद्योग मौसमी उद्योग है और सभी उत्पाद खराब होने वाले जिंस की ही तरह होते हैं क्योंकि वे टेलर मेड और विशेष डिजाइन, विशेष फैशन से जुड़े निर्यात हैं। अगर इस साल ऑर्डर रद्द होते हैं तो अगले साल उनका बहुत मामूली मूल्य रह जाएगा।'

प्रधानमंत्री को लिखे गए इसी तरह के एक पत्र में कॉन्फेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चेयरमैन टी राजकुमार ने सुझाव दिया कि सभी कच्चे मालों, डाई और केमिकल्स, इंटरमीडिएटरीज, स्पेयर और एसेसरीज को एंटी डंपिंग शुल्क और बुनियादी सीमा शुल्क से मुक्त किया जाना चाहिए।

एईपीसी ने इस बात की वकालत की है कि ज्यादातर क्षेत्र इस समय 3 से 4 प्रतिशत तक बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी मुनाफे पर काम कर रहे हैं और पूरी तरह से सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्यात लाभ पर निर्भर हैं। आयात में बाधाओं का हवाला देते हुए परिषद ने अनुरोध किया है कि निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत उपभोग न हो पाए सामान की वैधता की अवधि 6 महीने बढ़ाई जानी चाहिए। इसने एडवांस अथराइजेशन की वैधता की अवधि भी मौजूदा 12 महीने से बढ़ाकर 24 महीने करने की मांग की है। साथ ही निर्यात बाध्यताएं पूरी करने के लिए मौजूदा 18 महीने की जगह 36 महीने का वक्त दिए जाने की मांग की गई है।

निर्यातकों ने उद्योग विशेष के मुताबिक उठाए जाने वाले कदमों को विस्तार से बताया है, जो अन्य सरकारें उठा रही हैं और भारत को भी तत्काल उसके मुताबिक कदम उठाने की जरूरत है। परिधान क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टीटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एसके जैन ने कहा, 'परिधान के निर्यात में भारत का मुख्य प्रतिस्पर्धी बांग्लादेश इस समय मजदूरों व कर्मचारियों के 3 महीने के वेतन का वित्तपोषण मौजूदा कर्ज को 2 साल के लिए 2 प्रतिशत भुगतान पर कर रहा है। भारत को कम से कम इतना करने की जरूरत है। सरकार को मजदूरों व उद्योग दोनों की मदद करने की जरूरत है क्योंकि बैंक या ग्राहकों से धन आना रुक गया है।'

विश्व व्यापार संगठन के मुताबिक चीन, यूरोपीय संघ, बांग्लादेश और वियतनाम 2018 में विश्व के प्रमुख शीर्ष निर्यातक बने रहे। इन चारों की बाजारर हिस्सेदारी 72.3 प्रतिशत है। बांग्लादेश का परिधान निर्यात 2008 से 2018 के बीच तीन गुने से ज्यादा बढ़ा है।

कोरोना संकट शुरू होने के पहले से ही मुख्य आयातकों, खासकर संयुक्त अरब अमीरात की ओर से मांग बहुत कम हुई है। यह धारमा 2018 के आखिर में शुरू हुई, जब तमाम नई विनिर्माण इकाइयां यूएई के मुक्त बाजार क्षेत्र में स्थापित हुईं, जो भारत से कच्चा माल लेना पसंद करती हैं और तैयार माल का विरोध करती हैं।

- निर्यातकों ने कहा कि इस संकट से बर्बादी की ओर बढ़ रहा कारोबार
- जा सकती हैं लाखों नौकरियां, क्योंकि विनिर्माताओं को विदेशी ऑर्डर रद्द होने का डर
- भारतीय परिधान निर्यातकों को सबसे ज्यादा डर बांग्लादेश के निर्यातकों से
- अगले 3 महीने के वेतन भुगतान में बांग्लादेश सरकार की तरह ही छूट चाहते हैं भारतीय निर्यातक
- चीन, यूरोपीय संघ, बांग्लादेश और वियतनाम 2018 में विश्व के प्रमुख शीर्ष निर्यातक

बंदी से एनसीआर और मुंबई को सबसे ज्यादा नुकसान

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 3 अप्रैल

एनसीआर में बर्कलेज ने दिल्ली और आसपास के शहरों नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद को शामिल किया है

बर्कलेज के हाल के शोध में पाया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और मुंबई को 21 दिन की देशबंदी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान होगा। उसके बाद बेंगलूरु, हैदराबाद और पुणे का स्थान है।

वैश्विक महामारी कोरोनावायरस

बर्कलेज के मुख्य अर्थशास्त्री राहुल बाजोरिया द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में एशिया प्रशांत इलाकों का अध्ययन किया गया है, जहां इस समय लॉकडाउन चल रहा है और इससे प्रति सप्ताह 1 अरब डॉलर से 1.7 अरब डॉलर प्रति सप्ताह का नुकसान हो रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'हमने पाया है कि क्वालालंपुर, मनीला, दिल्ली (एनसीआर) और मुंबई में बंदी की वजह से प्रति सप्ताह कुल आर्थिक नुकसान 1 अरब डॉलर से 1.7 अरब डॉलर के बीच होगा।'

मेगासिटी उन शहरों या शहरी क्लस्टर को कहते हैं, जिनमें 1 करोड़ से ज्यादा आबादी होती है। बहरहाल एशिया प्रशांत की छोटी, खुली अर्थव्यवस्था की प्रकृति को देखते हुए बर्कलेज ने इस परियोजना के लिए परिभाषा नरम की है, जिससे बड़े आर्थिक केंद्रों या प्रमुख महागरों व क्षेत्रों को शामिल किया जा सके, जहां का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े उपलब्ध थे। बर्कलेज ने एनसीआर में दिल्ली और सैटेलाइट टाउनों नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद को शामिल किया है। लॉकडाउन की स्थिति में शहरों को आर्थिक हिसाब से ज्यादा नुकसान हो रहा है। वहीं बर्कलेज का मानना है कि अगर यह लंबा चलता है तो अन्य शहरों में भी अनिश्चितता बढ़ेगी।

बीएस सूडोकू 3706

परिणाम संख्या 3605

				3				
		9			7		2	
				4	2			
		2			4	3	8	
	3					2	9	
	4			5				
	2			6			4	
		5					1	
	7	4				8		

1	6	4	2	7	8	9	3	5
3	7	8	6	9	5	1	2	4
5	9	2	4	3	1	6	8	7
8	1	3	5	4	9	7	6	2
2	5	7	3	1	6	8	4	9
6	4	9	7	8	2	5	1	3
7	8	1	9	2	3	4	5	6
4	3	5	1	6	7	2	9	8
9	2	6	8	5	4	3	7	1

कैसे खेलें?

हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

आसान ★★☆☆☆

प्रतीकों पर जोर देने के बजाय गरीबों की मदद करे सरकार

अर्चिस मोहन
नई दिल्ली, 3 अप्रैल

विपक्षी दलों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में जबकि देशव्यापी लॉकडाउन के आर्थिक दुष्प्रभावों से पीड़ित लोगों को राहत देने वाले उपाय घोषित करने की आवश्यकता है, तब वह प्रतीकात्मकता का सहारा ले रहे हैं। देश मे कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए सरकार ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी।

शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे पांच अप्रैल को रात 9 बजे अपने घरों की बत्तियां पांच मिनट के लिए बंद कर दें और मोमबत्ती, दिए या मोबाइल के टॉर्च से रोशनी करें ताकि कोरोनावायरस से इस लड़ाई में एकजुटता दिखाई जा सके।

विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि दुनिया भर के नेता जहां कोरोनावायरस के खराब असर और उससे उपजे संकट से निपटने के आर्थिक उपायों पर चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि लोगों को किस प्रकार राहत पहुंचाई जा रही है, वैसे में भारतीय प्रधानमंत्री प्रतीकात्मक कदमों में उलझे हुए हैं

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया, 'हम आपकी बात सुनेंगे और 5 अप्रैल को दिये जलाएंगे लेकिन बदले में कृपया आप हमारी और महामारी विशेषज्ञों तथा अर्थशास्त्रियों की बात सुनिए। हमें आपसे दूसरी वित्तीय कार्य योजना के बारे में सुनने की अपेक्षा थी ताकि उन गरीबों की आजीविका को राहत मिल सके जिन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 25 मार्च की वित्तीय कार्य योजना में पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया।'

चिदंबरम ने आगे लिखा, 'हर कामकाजी आदमी और औरत, कारोबारी से लेकर दैनिक मजदूर तक सभी को आशा थी कि आप आर्थिक गिरावट को थामने वाली और आर्थिक विकास के इंजन में नई जान फूंकने वाली घोषणाएं करेंगे। लोग दोनों मोर्चों पर निराश हुए हैं। प्रतीकवाद महत्त्वपूर्ण है लेकिन गंभीर विचार विमर्श भी उतना ही जरूरी है।' चिदंबरम यह अनुमान जता चुके हैं कि कोविड-19 से लड़ने के लिए अर्थव्यवस्था में 5 से 6 लाख करोड़ रुपये की राशि डालनी होगी।

मार्क्सवादी क युनिस्ट पार्टी नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि मौजूदा चुनौतियों से प्रतीकवाद के सहारे नहीं निपटा जा सकता। उन्होंने कहा, 'कृषि और खेती का काम पूरी तरह ठप हो गया है क्योंकि केंद्र कोई योजना नहीं तैयार कर सका। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन के बाद थोक बाजारों में आवक 70 प्रतिशत तक गिरी है।'

येचुरी ने कहा कि दूध खरीद भी बहुत गिर गई है। उन्होंने कहा कि तमाम विपक्षी दल राज्य सरकारें व अन्य लोग कह चुके हैं कि ऐसे भटकाने वाले कदमों से लाभ नहीं होगा। केंद्र के ढीलेढाले रवैये के कारण पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरण नहीं खरीदे जा रहे जिसका खमियाजा स्वास्थ्य कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि इसकी जवाबदेही कौन लेगा?

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 38

कोविड और उसके बाद

किसी भी वृद्धि वक्र के तीन चरण होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इन दिनों कोविड-19 के मामले में देखने को मिल रहा है। सबसे पहला चरण वह है जहां नए मामले रोज स्थिर या तेज गति से बढ़ते हैं। दूसरा चरण वह जब वृद्धि दर में तो गिरावट आने लगती है लेकिन कुल मामलों की तादाद अब भी बढ़ रही होती है और वक्र सपाट हो जाता है। तीसरा चरण वह है जब नए मामलों की तादाद कम होनी शुरू हो जाती है। दुनिया भर में कोविड-19 के 10 लाख से अधिक मामलों में से 80 प्रतिशत दुनिया के जिन 10 शीर्ष देशों में हैं उनमें से सात में यह दूसरे या तीसरे चरण में है। केवल अमेरिका, ब्रिटेन और तुर्की अपवाद हैं। बाकी देखा जाए तो लगभग पूरी दुनिया कोविड-19 के वक्र के पहले चरण के अंत में है।

भारत भी उसी स्थिति में है या शायद तबलीगी जमात वाली घटना नहीं होती तो वह उसी स्थिति में होता। यदि हम मानकों का पालन करें और 14 मार्च को जब देश में कोविड के 100 मामले हुए, तब से इसका विस्तार देखें तो 9 दिन में यह 500 तक पहुंचा। लॉकडाउन के बाद के शुरुआती 10 दिन में यह पांच गुना बढ़कर 2,500 हो गया। यदि लॉकडाउन के शेष 11 दिन में यह एक बार फिर पांच गुना हो जाता है तो अप्रैल के मध्य तक देश में कोविड-19 के कुल 12,000 मामले होंगे। अगर हम लॉकडाउन के बावजूद तब तक दूसरे चरण की ओर निर्णायक ढंग से नहीं बढ़े तो वाकई बुरी खबर होगी। आश्चर्य नहीं कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात कही है।

अच्छी बात यह है कि शायद हम कभी आबादी और मामलों के उस अनुपात पर न पहुंचे जिस अनुपात पर पश्चिमी यूरोप के देश हैं। यूरोप में हर पांच-छह करोड़ की आबादी पर एक लाख मामले हैं। यदि उस स्थिति को भारत के बारे में रखकर देखें तो 20 लाख मामलों के आसपास ठहरेगा। जबकि अभी पूरी दुनिया में कुल मिलाकर 10 लाख मामले सामने आए हैं। इसके बावजूद हमारे देश में स्वास्थ्य संक्रमण को काफी हद तक रोका जा सकता है। बुरी खबर केवल इतनी है कि ये नियंत्रण अचानक समाप्त नहीं हो जाएंगे। हल्का फुल्का नियंत्रण एक वर्ष तक चलता रहेगा। हल्के नियंत्रण भी अर्थव्यवस्था को उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे जितना कि पूर्णकालिक लॉकडाउन। ये नियंत्रण भी उपभोक्ताओं के विश्वास और खपत को प्रभावित करेंगे। चीन में ज्यादातर लॉकडाउन समाप्त होने के बाद और बहुत कम नए मामले सामने आने के बाद भी विनिर्माण गतिविधियां सामान्य स्तर का 80 फीसदी हैं। सेवा क्षेत्र भी काफी कमजोर है। थिएटर, मॉल और रेस्टोरेंट आदि धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं लेकिन वहां भी रोज से 50 फीसदी कम कामकाज हो रहा है।

इसे पूरी तरह ठीक होने में लंबा समय लगेगा। अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचेगा। खासतौर पर सेवा क्षेत्र के हालात सुधरने में। हालात तीन सप्ताह में सुधरने वाले नहीं हैं। कंपनियों के मुनाफे में भी भारी कमी आएगी। तमाम क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण आएगा। मजबूत बैलेंस शीट प्रतिस्पर्धी बढ़त दिलाने वाली साबित होगी। बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। कई जगह दिवालिया और छंटनी जैसी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। खासतौर पर छोटे और मझोले उपक्रमों में ऐसा देखने को मिलेगा। बैंकों के फंसे हुए कर्ज में इजाफा होगा। चूंकि बैंक पहले ही जोखिम से बच रहे हैं तो ऐसे में नियामकीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऋण वितरण में रुकावट न आए। पूरी अर्थव्यवस्था में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। वित्त वर्ष 2021 में मुनाफों का अनुमान लगाना मुश्किल होगा और ज्यादातर कंपनियों के लिए यह वर्ष एक गंवाया हुआ वर्ष बनकर रह जाएगा। दुनिया भर की ज्यादातर कंपनियां नकदी बचाने में लग जाएंगी। जोखिम से बचने वाले ऐसे माहौल में गुणवत्तापूर्ण चीजें बची रह जाएंगी। कोई निवेशक शासन के मुद्दों और बैलेंस शीट के तनाव की अनदेखी नहीं कर पाएगा।

आगे की राह अनिश्चित है। लेकिन मौजूदा लॉकडाउन के कारण भारत तथा दुनिया के अन्य देशों की आर्थिक गतिविधियों में भारी संकुचन आएगा। लॉकडाउन कम होने और नियंत्रण घटने के बाद भी स्थितियों में धीरे-धीरे ही सुधार होगा। ऐसे में सरकार के आर्थिक नीति को लेकर आक्रामक और साहसी होने की परीक्षा होगी।

अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए हमें तमाम राजकोषीय और मौद्रिक नीति समर्थन प्रदान करना होगा। निवेशक भी उन देशों और बाजारों का ही रुख करेंगे जहां प्रशासन पेशकदमी करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की राजकोषीय प्रतिक्रिया बहुत सीमित नजर आती है। यह समय राजकोषीय स्थिति की चिंता करने का नहीं है। ऐसे माहौल में जहां अन्य देश जीडीपी के 10 फीसदी के बराबर राजकोषीय सहयोग दे रहे हैं वहां भारत द्वारा केवल 5 फीसदी की मदद बहुत कम है। देश में वृद्धि और रोजगार को बढ़ावा देने में छोटे और मझोले उपक्रमों के महत्त्व को देखते हुए, सेवा क्षेत्र पर हमारी निर्भरता के मद्देनजर और सामाजिक सुरक्षा ढांचे की कमी के कारण हम खासतौर पर संकट में हैं। सरकार को साहसी कदम उठाने होंगे।

सुविधा बुनियादी ढांचे की कमी जल्द उजागर हो सकती है। सरकार की प्रतिक्रिया में हमारी और आपकी भूमिका सर्वाधिक है जबकि सरकार की ओर से परीक्षण और राहत पैकेज काफी कम हैं। बल्कि संपूर्ण लॉकडाउन के कारण फैक्टरियां बंद हुईं, आय का नुकसान हुआ, प्रवासियों के लिए संकट उत्पन्न हुआ। ऐसे में लॉकडाउन के साथ व्यापक भुगतान की तत्काल घोषणा की जानी चाहिए थी। कोई कदम उठाने के पहले समग्र सोच विचार नहीं करना आदत बनती जा रही है। सन 2016 में नोटबंदी के बाद नई मुद्रा की कमी हो गई थी। हालात तब और बिगड़ गए जब अलग-अलग आकार के नोटों के कारण एटीएम को नए सिरे से व्यवस्थित करना पड़ा। अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर हो रहा है? शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि पिछले महीने इसका बहुत गहरा असर हुआ। इसे पहले की मंदी से जोड़कर देखें तो वाहनों की बिक्री में 50 फीसदी कमी आई, वस्तु एवं सेवा कर राजस्व में 20 फीसदी गिरावट, पेट्रोल और डीजल की खपत में 20 फीसदी कमी और बिजली की खपत में 30 फीसदी कमी आई। पूरे वर्ष का प्रत्यक्ष कर राजस्व दो वर्ष पहले के स्तर पर है जबकि उस वक्त अर्थव्यवस्था आज से 15 फीसदी कमतर थी। कुछ आंकड़े 2008 के वित्तीय संकट से भी बुरे रह सकते हैं।

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

राजस्व के आंकड़े कमजोर पड़ने और संकट से निपटने के लिए व्यय बढ़ने पर राजकोषीय तनाव बढ़ेगा। ऐसे में हम तीन दशक पुरानी राजकोषीय स्थिति में पहुंच सकते हैं। वित्त मंत्री के पास एक उपाय था वह बजट में उल्लिखित पूंजीगत व्यय को कम कर सकती थीं लेकिन चूंकि अब वह जीडीपी का बहुत मामूली हिस्सा है इसलिए उससे भी मदद नहीं मिलेगी। हमें एक या दो तिमाही प्रतीक्षा करनी होगी जब अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी और उसके बाद धीमी गति से सुधार की शुरुआत होगी। धीमी इसलिए क्योंकि बंद पड़ी फर्म को दोबारा काम शुरू करने में वक्त लगेगा, राजकोषीय तंगी बनी रहेगी और कारोबारी माहौल भी अनुकूल नहीं होगा। छंटनी और कटौती के कारण आम परिवारों की क्रय शक्ति कमजोर होगी और निवेश पर भी इसका असर होगा। दोहरे घाटे की समस्या एक बार फिर खड़ी हो जाएगी। मांग में कमी ने पहले ही जिंस कीमतों को प्रभावित किया है और वे 25 से 30 फीसदी तक गिर गई हैं। भारी कारोबारी कर्ज भी वित्तीय क्षेत्र का तनाव बढ़ा सकता है। नई सदी का पहला दशक संकट में समाप्त हुआ। दूसरा दशक भी धीमी वृद्धि के साथ उसी हालत में रहा। तीसरे दशक का उत्तरार्द्ध तो बीते दो दशकों से भी बुरा साबित होता दिख रहा है। कृपया अंधेरा होने पर अपने दीये जला लें।

अजय मोहंती

लॉकडाउन के बाद अब आगे क्या?

देशबंदी ने हमारी अर्थव्यवस्था को खासतौर पर संवेदनशील बना दिया है। इसे लेकर पहली राजकोषीय प्रतिक्रिया अत्यंत साहसी होनी चाहिए। विस्तार से बता रहे हैं **आकाश प्रकाश**

दुनिया भर में बंदी का दौर चल रहा है। तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने किसी न किसी तरह का लॉकडाउन लागू कर रखा है। ऐसे में किसी भी निवेशक के मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से आएगा कि यह लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा और इसकी क्या कीमत चुकानी होगी?

कोविड-19 महामारी वैश्विक अर्थव्यवस्था से एक बड़ी कीमत वसूल कर चुकी है। दुनिया भर में 6 लाख से अधिक लोग इसके शिकार हो चुके हैं और 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी का तेजी से विस्तार हो रहा है। कई जगह तो हर तीन दिन में इसके मामले दोगुना हो रहे हैं। दुनिया मंदी की ओर बढ़ रही है और अधिकांश संकेतक बता रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियां तेजी से घटी हैं। यह गिरावट वैश्विक वित्तीय संकट के दौर से भी गहरी है। कई टीकाकारों का कहना है कि अमेरिका के जीडीपी में तिमाही आधार पर 25 आधार अंकों की कमी आ सकती है। यूरोप में भी ऐसी ही गिरावट आने की बात कही जा रही है। अधिकांश देशों में वृद्धि नकारात्मक रहेगी। मैंने कभी आर्थिक गतिविधियों में ऐसी गिरावट नहीं देखी थी जैसी चीन में और उसके बाद पूरी दुनिया में नजर आई।

लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करेगा। अब सवाल यह है कि यह कब तक चलेगा? अधिकांश देश वायरस के प्रसार को लेकर बहुत देर से हरकत में आए इसलिए उन्हें लॉकडाउन लागू करना पड़ा। वे ऐसा करके ही बीमारी पर नजर रख पाएंगे। यदि विभिन्न देशों ने पहले प्रतिक्रिया दी होती और सिंगापुर और ताइवान की तरह ज्यादा से ज्यादा जांच की होती तो यूं लॉकडाउन न करना पड़ता।

यहां बात एकदम साफ है। हमें किसी संक्रमित व्यक्ति से संक्रमित होने वालों की तादाद कम करनी होगी। यदि हम इसकी दर एक से नीचे लाने में कामयाब रहे तो वायरस का विस्तार कम होने लगेगा। फिलहाल यह दर 2 से 3 के बीच है। लॉकडाउन का लक्ष्य इसे घटाकर एक के नीचे लाना है। एक बार ऐसा हो गया तो इसे शिथिल किया जा सकता है। तब कड़े नियम शिथिल किए जा सकते हैं और अधिक सहज नीतियां अपनाई जा सकती हैं। इससे बीमारी समाप्त तो नहीं होगी लेकिन संक्रमण के मामले स्थिर हो जाएंगे और इनमें अचानक बढ़ोतरी नही होगी। हर देश ऐसी स्थिति से बचना चाहता है।

एक बार लॉकडाउन समाप्त होने के बाद टीका बनने तक हल्के नियंत्रण से काम चल जाएगा। यह भी संभव है कि हमारा शरीर मजबूत प्रतिरक्षा विकसित कर ले ताकि इसका प्रसार आसानी से रोका जा सके। टीका बनने में 12-15 महीने का समय लग सकता है।

नीतिगत राह स्पष्ट है। संक्रमण दर सीमित होने तक गंभीर सामाजिक नियंत्रण और लॉकडाउन अपनाने होंगे। बाद में सीमित नियंत्रण हो, बड़े कार्यक्रम न आयोजित किए जाएं, यात्राएं सीमित हों, बुजुर्ग सामाजिक दूरी का पालन करें और जरूरत पड़ने पर कड़ाई से जांच हो। ऐसा करने से हमें जरूरी समय मिल जाएगा और अर्थव्यवस्था को भी कम नुकसान होगा।

अच्छी बात है कि कड़े सामाजिक नियंत्रण और लॉकडाउन ने इस बीमारी के प्रसार को सीमित करने का काम किया है। चीन ने 23 जनवरी को लॉकडाउन किया जिसका असर पांच दिन में नजर आने लगा था। चीन ने हुवेई प्रांत के बाहर इसका संक्रमण दो सप्ताह में रोक दिया और एक महीने में हुवेई में भी यह खत्म हो गया। इटली में भी लॉकडाउन ने नए संक्रमण सीमित कर दिए हैं।

कह सकते हैं कि यदि कोई देश एक महीने के भीतर सफलतापूर्वक सामाजिक दूरी और लॉकडाउन का पालन कर ले तो

केसीआर सरकार के कल्याण कार्यक्रमों को फंड की दरकार

के चंद्रशेखर राव (केसीआर) के नेतृत्व वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने उसे वर्ष 2018 में दोबारा सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। यह एक बंपर चुनावी फसल थी। पार्टी को करीब 47 फीसदी मत मिले थे जो 2014 में हासिल मत फीसदी से 12.6 फीसदी अधिक थे। इसका नतीजा यह हुआ कि तेलंगाना में टीआरएस को पहले से 25 अधिक सीटें मिलीं। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने चुनाव में अपनी पूरी जान लगा दी थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस का मत प्रतिशत पहले से जरूर बढ़ा लेकिन उसकी सीटों की संख्या 21 से घटकर 19 रह गईं। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तो महज एक सीट ही जीत पाई और उसके प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव हार गए। हैदराबाद के पुराने शहर को एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है लेकिन उसे भी झटका लगा। हालांकि वह अपनी सात सीटें बनाए रखने में सफल रही लेकिन उसका मत प्रतिशत पिछले चुनाव से कम रहा। केसीआर को शानदार जीत दिलाने का काम उनके कल्याणकारी शासन ने ही किया। लेकिन बिलों के बढ़ते जाने और राजस्व संग्रह में गिरावट का सिलसिला शुरू होने के बाद अब खतरे की घंटियां बजने लगी हैं।

सियासी हलचल
आदिति फडणीस

कोविड महामारी की चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मुख्यमंत्रियों ने अधिक फंड जारी किए जाने की मांग रखी। लेकिन इस दौरान केसीआर का लहजा अधिक तेज एवं हताशा से भरा था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को तेलंगाना के वाजिब हिस्से से भी अधिक फंड जारी करना चाहिए क्योंकि वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों के पूल में से राज्यों को देय अंश को 42 फीसदी से घटाकर 41 फीसदी कर दिए जाने से तेलंगाना को काफी नुकसान हुआ है। केसीआर का यह भी कहना था कि अपने वित्त का समझदारी से इस्तेमाल करने वाले तेलंगाना को केंद्रीय कर, राज्य आपदा राहत कोष, स्थानीय निकाय कोष अनुदान एवं अन्य अनुदानों में केंद्र सरकार को राज्य का वैध हिस्सा देना चाहिए। इसके अलावा जीएसटी क्षतिपूर्ति में भी तेलंगाना को केंद्र से समुचित भुगतान की मांग रखी। केसीआर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ऐसा नहीं होने पर तेलंगाना को अपनी कल्याणकारी नीतियों के लिए फंड जुटाने में समस्या होगी।

सच तो यह है कि 2010-2015 के दौरान केंद्र सरकार से तेलंगाना को कुल 46,740 करोड़ रुपये निर्गत किए गए। अगले पांच वर्षों में यह राशि बढ़कर 1,06,606 करोड़ रुपये हो गई। इस तरह वर्ष 2015-2020 में तेलंगाना को केंद्र से मिली राशि 2010-15 के दौरान जारी किए गए पैसे से करीब 128 फीसदी अधिक है।

जीएसटी क्षतिपूर्ति को हरेक दो महीने पर जीएसटी उपकर कोष से राज्यों के लिए जारी किया जाना था। लेकिन जीएसटी उपकर संग्रह में गिरावट आने से यह क्षतिपूर्ति अक्टूबर के बाद से राज्यों को नहीं दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे पर संसद में बयान देने के अलावा बजट के बाद हैदराबाद में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में भी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार तेलंगाना के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रही है, अन्य राज्यों की भी ऐसी ही शिकायतें हैं।

गत 8 मार्च को तेलंगाना के वित्त मंत्री हरीश राव ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट विधानसभा में पेश किया था। उसमें नए वित्त वर्ष के लिए 44,245 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान रखा गया था जो वर्ष 2019-20 के संशोधित बजट अनुमान से 41.2 फीसदी अधिक है। वर्ष 2020-21 के लिए पूंजी आवंटन 22,061 करोड़ रुपये किया गया है जो 2019-20 के संशोधित अनुमान से 67.6 फीसदी अधिक है। इस बढ़े हुए आवंटन की वजह यह है कि जलापूर्ति, साफ-सफाई, आवास एवं शहरी विकास के मदों में व्यय 10,161 करोड़ रुपये यानी 2067 फीसदी की भारी वृद्धि की गई है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार ने कई और कल्याण योजनाएं शुरू करने का फैसला किया है जिनके लिए भुगतान करना होगा।

संभवत: भारत के किसी भी अन्य राज्य की कल्याणकारी वचनबद्धता तेलंगाना सरकार के समान नहीं है। कोविड-19 संकट के समय भी तेलंगाना सरकार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को 12 किलो चावल और 1,500 रुपये की नकद सहायता दे रही है। बाहरी राज्यों से आकर तेलंगाना में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को भी सरकार की तरफ से 12 किलो चावल और 500 रुपये नकद राशि दी जा रही है। यह सहायता छोटी जोत वाले किसानों को मिलने वाले सालाना 10,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान के अतिरिक्त है। सरकार चुनावों के समय लोगों से किए गए अन्य वादों को भी पूरा कर रही है।

कोविड-19 संकट के दौरान जमीन की बिक्री का पंजीकरण शून्य हो चुका है। सिनेमाघर भी बंद पड़े हुए हैं, लिहाजा सरकार को मनोरंजन कर से भी कोई राजस्व नहीं मिल पा रहा है। शराब की दुकानें बंद होने से आबकारी राजस्व भी नहीं आ रहा है। तेलंगाना के बजट के अनुसार 2020-21 में राज्य को आबकारी राजस्व के तौर पर ही 16,000 करोड़ रुपये मिलेंगे जो 2019-20 के संशोधित अनुमान से करीब 27 फीसदी अधिक है। इसी तरह बजट में स्टांप शुल्क एवं भूमि पंजीकरण से 10,000 करोड़ रुपये मिलने का प्रावधान किया गया है जो पिछले वित्त वर्ष से 55 फीसदी अधिक है। लेकिन कोविड-19 महामारी का प्रकोप फैलने के बाद किसी को नहीं मालूम नहीं है कि वित्त वर्ष 2020-21 में क्या होने जा रहा है?

मौजूदा हालात में सभी राज्यों को अपना वित्त पुनर्गठित करना होगा। लेकिन तेलंगाना के लिए यह समस्या कहीं अधिक बड़ी है। इसकी वजह यह है कि तेलंगाना सरकार ने जिस राह पर चलने का वादा किया है वह उससे दूर नहीं जा सकती है, अगर वह ऐसा करती है तो उसे बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री केसीआर और उनकी टीम को इस गतिरोध से निकलने के लिए वित्तीय जादू की जरूरत पड़ेगी।

कानाफूसी

फर्जी खबरों पर कड़ाई

उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस के बढ़ते आंकड़ों के बीच राज्य सरकार ने प्रदेश के सूचना विभाग में एक विशेष इकाई का गठन किया है जो कोविड-19 को लेकर फैल रही फर्जी खबरों पर नजर रखेगी। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के हालिया निर्देशों का हवाला दिया है। 20 मार्च को जारी उस निर्देश में कहा गया था कि सोशल मीडिया कंपनियां अपने मंच पर फर्जी खबरों का प्रसार रोकें, जागरूकता बढ़ाएं और गलत जानकारी को वहां से हटाएं। उनसे यह भी कहा गया कि वे अपने मंच पर वास्तविक खबरों का ही प्रसार करें। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ऐसे मामलों में जरा भी सहिष्णुता नहीं दिखाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

श्रेय की होड़

देश के दूसरी बार क्रिकेट विश्वकप जीतने की नौवीं वर्षगांठ के मौके पर विजेता टीम के सदस्य रहे और वर्तमान में लोकसभा सदस्य गौतम गंभीर एक बार फिर तत्कालीन क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जिक्र पर उखड़े नजर आए। उनका इशारा इस ओर था कि धोनी उस जीत का अधिकांश श्रेय ले गए। गंभीर ने एक वेबपोर्टल पर जारी ट्वीट का हवाला दिया जिसमें धोनी को विश्व कप फाइनल में विजयी छक्का लगाते हुए दिखाया गया। गंभीर ने लिखा, 'सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा ईएसपीएनक्रिकइन्फो : विश्वकप 2011 समूचे भारत, समूची भारतीय टीम और सहायक स्टाफ ने जीता था। वक्त आ गया है कि आप उस छक्के के मोह से बाहर निकलें।' दरअसल स्वयं गंभीर ने विश्व कप फाइनल में 97 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी और उन्हें लगता है कि धोनी के छक्के ने उनकी पारी का श्रेय भी छीन लिया।

आपका पक्ष

कोरोना की जांच बेहद जरूरी

कोरोना के तेजी से बढ़ते खतरे को देखते हुए कई देशों ने लॉकडाउन किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना को रोकने के लिए सिर्फ लॉकडाउन कारगर तरीका नहीं है बल्कि लोगों की जांच भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तब कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने लगेगा। कोरोना के संक्रमित होने की गति बहुत तेज है। आमतौर पर किसी दूसरे फ्लू की इन्फेक्शन दर 0-1 होती है। अर्थात एक संक्रमित व्यक्ति अन्य किसी एक ही शख्स को संक्रमित करता है। कोरोना की यही दर 4-6 है। इसलिए लॉकडाउन के दौरान भी लोगों की जांच बहुत जरूरी है। भारत में अभी तक बहुत कम लोगों की जांच की गई है। इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। इससे साफ होगा कि संक्रमित लोगों की

श्रीनगर में 14 दिनों के क्वारंटाइन के बाद अपने घर लौटतीं छात्राएं -पीटीआई

वास्तविक संख्या कितनी है। इटली ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 25 से 29 साल के उम्र वाले अधिकतर लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे थे। लेकिन जब उसकी जांच हुई तो उसमें कई लोग संक्रमित पाए गए। इसलिए भारत में भी जब अधिक से अधिक लोगों की जांच की जाएगी तो वास्तविक आंकड़ा सामने आएगा।

रूबी सिंह, गोरखपुर

सफाईकर्मियों को मिलें सुरक्षा किट

कोरोना महामारी के दौरान बहुत से लोग अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं। देश में मीडियाकर्मियों, स्वास्थ्यकर्मियों तथा पुलिसकर्मियों की हर तरफ सराहना हो रही है। सब्जीवाले, सफाईकर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे लोग न जाने कितने लोगों के संपर्क में आते हैं, जिनमें से कोई भी संक्रमित हो सकता है। इनके पास सुरक्षा किट भी नहीं है। इनके संक्रमित होने का अधिक खतरा है। इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को मास्क एवं दस्ताने उपलब्ध कराने चाहिए।

भूपेंद्र कुलदीप सिंह, सोनीपत

गौरेया से कुदरत का सौंदर्य, इन्हें बचाएं

पिछले महीने 20 मार्च को विश्व गौरेया दिवस मनाया गया। यह चिड़ियों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया गया। मनुष्य अपने सुख-सुविधाओं के लिए प्रकृति का विनाश करता गया तथा वन्य जीव, पशु-पक्षियों की रक्षा करना भूल गया। इससे कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गईं। प्रकृति ने प्राणी जाति के लिए एक चक्र बनाया है। इसमें हर जीव-जंतु, पक्षियों का होना जरूरी है। लेकिन आज मनुष्य ने आधुनिकता और भौतिकतावाद की दौड़ में अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ पशु, पक्षियों और अन्य सभी प्राणी का जीवन संकट में डाल दिया है। प्रदूषण, मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगों आदि से पक्षियों का जीवन संकट में है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

नई दिल्ली | 4 अप्रैल 2020 शनिवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

कोरोना से जंग को तैयार सेना

सेना की जांच सुविधाएं, 15,000 बेड, आईसीयू और सैन्य स्कूल कराए जाएंगे उपलब्ध

अजय शुक्ला

कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रीय प्रयासों को 'युद्ध' की संज्ञा दी जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सेना के अतिरिक्त चिकित्सा एवं लॉजिस्टिक संसाधनों का इस्तेमाल सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन की मदद में किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सशस्त्र बल पहले ही मुंबई, जैसलमेर, जोधपुर, हिंडन, मानेसर और चेन्नई में छह क्वारंटीन केंद्र बना चुके हैं। इसके अलावा सेना देश भर में सशस्त्र बलों के 51 अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) उपलब्ध कराएगी।

रक्षा मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया, 'इन अस्पतालों में से कुछ कोलकाता, विशाखापत्तनम, कोच्चि, हैदराबाद के निकट डूंडीगल, बेंगलूरु, कानपुर, जैसलमेर, जोरहाट और गोरखपुर में हैं।'

रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि इनके अलावा 15 अन्य सैन्य अस्पतालों को जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए तैयार रखा गया है। इनमें संयुक्त रूप से कोविड-19 के मरीजों के लिए करीब 15,000 बेड होंगे। सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में सहयोग के लिए 8,500 डॉक्टर और सहायक स्टाफ मुहैया कराने की पेशकश की है।

कोरोनावायरस की जांच में तेजी आ रही है, इसलिए सशस्त्र बलों के अस्पतालों में पांच वायरल जांच लैब को नैशनल ग्रिड का हिस्सा बनाया गया है। सशस्त्र बलों के अस्पतालों की इन लैब में कोविड-19 की जांच की सुविधाएं हैं।

कोरोना पर मंत्रिसमूह की बैठक की अध्यक्षता करते रक्षा मंत्री

- सशस्त्र बल ने मुंबई, हिंडन, जैसलमेर, जोधपुर, मानेसर व चेन्नई में क्वारंटीन केंद्र बनाए
- देश भर में सशस्त्र बलों के 51 अस्पतालों में आईसीयू उपलब्ध कराएगी सेना
- सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने 8,500 डॉक्टर और सहायक स्टाफ मुहैया कराने की पेशकश की
- 15 अन्य सैन्य अस्पतालों को तैयार रखा गया

मंत्रालय ने कहा, 'इनमें सेना अस्पताल (रिसर्च ऐंड रेफरल) दिल्ली कैंट, एयर फोर्स कमांड हॉस्पिटल बेंगलूरु, आर्मड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, और कमांड हॉस्पिटल उधमपुर शामिल हैं। छह अन्य अस्पतालों में कोविड-19 की जांच के लिए जरूरी सुविधाएं तैयार की की जा रही हैं।'

सशस्त्र बलों के पहले से चालू क्वारंटीन केंद्र पहले ही 1,737 मरीजों को संभाल चुके हैं। इन लोगों में से 403 को घर जाने को कहा जा चुका है, जबकि कोविड-19 के तीन पॉजिटिव लोगों को आगे के इलाज के लिए नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल भेजा जा चुका है। इन तीन मरीजों में दो हिंडन और एक मानेसर से आया था।

सेना का मुख्य कार्य भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना है, लेकिन यह मुश्किल घड़ी में सरकार को नागरिक मामलों में भी मदद देती है। सेना जम्मू-कश्मीर जैसे अशांत क्षेत्रों कानून व्यवस्था और नागरिक प्रशासन बहाल करने के अलावा सरकार के कहने पर प्राकृतिक आपदा और महामारी को नियंत्रित करने में भी मदद देती है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने मीडिया से कहा, 'सेना सरकार और लोगों की मदद के लिए पूरी तरह तैयार है।' रावत ने इस समय लॉकडाउन और बाद में गर्मियों की छुट्टी के कारण बंद सैन्य स्कूलों के परिसरों का इस्तेमाल क्वारंटीन केंद्र बनाने में किए जाने की पेशकश की है।

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने आवश्यक आपूर्ति, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों के परिवहन के लिए अपने विमानों का बेड़ा तैयार कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, 'अब तक करीब 60 टन सामान विमानों के जरिये देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जा चुका है। देश में बहुत सी जगहों पर 28 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और 21 हेलिकॉप्टर तैयार खड़े हैं।'

इस बीच भारतीय वायु सेना की विशेष उड़ानों के जरिये भारतीय नागरिकों को लाया गया है और 25 टन से अधिक चिकित्सा सामग्री पहुंचाई गई है। मंत्रालय ने कहा, 'एक सी-17 ग्लोबमास्टर 3 चीन में 15 टन चिकित्सा सामग्री पहुंचा चुका है और वापसी में 125 लोगों को निकालकर ला चुका है। इन लोगों में भारतीय नागरिक और कुछ मित्र देशों के नागरिक शामिल थे।'

एक आईएएफ सी-17 ग्लोबमास्टर 3 ईरान गया था और वहां फंसे 58 भारतीयों को लेकर आया था। इस उड़ान के जरिये कोविड-19 की जांच के लिए 529 नमूने लाए गए थे।

भारत हमेशा हिंद महासागर क्षेत्र के छोटे देशों की मदद करता रहा है। इसी क्रम में सी-130जे सुपर हर्क्यूलिस विमान 6.2 टन दवाएं लेकर मालदीव पहुंचा था। रक्षा मंत्रालय ने कहा, 'आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की एक टीम 13 से 21 मार्च तक मालदीव में गई थी और वहां उनकी खुद की जांच, इलाज और क्वारंटीन सुविधाएं स्थापित करने में मदद दी। इस टीम में पांच डॉक्टर, दो नर्सिंग अधिकारी और सात पैरामैडिकल स्टाफ शामिल था।'

नौसेना ने तटीय पड़ोसियों की मदद के लिए छह युद्धक पोत तैयार कर लिए हैं। इसके अलावा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान में तैनाती के लिए नौसेना की पांच चिकित्सा टीम तैयार हैं।

इस बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने पांच परत का नैनोटेक्नोलॉजी फेस मास्क बनाया है, जिसे एन99 नाम दिया गया है। डीआरडीओ ने अपना दैनिक मास्क उत्पादन बढ़ाकर 20,000 कर दिया है। डीआरडीओ वेंटिलेटर में भी कुछ बदलाव कर रहा है ताकि एक मशीन एक समय में चार मरीजों को सेवाएं दे सके।

बिगबास्केट और ग्रोफर्स का भर्तियों पर जोर

समरीन अहमद

ऑनलाइन ग्रॉसरी (किराना) स्टार्टअप बिगबास्केट और ग्रोफर्स ने पुराने ऑर्डर को भेजने और नए ऑर्डर लेने के लिए अपने गोदाम (वेयरहाउस) में काम करने वाले और लोगों के घरों तक सामान पहुंचाने वाले कर्मियों की भर्ती करने के लिए तेजी दिखाई है। बेंगलूरु का स्टार्ट-अप बिगबास्केट जहां 10,000 लोगों की भर्ती करेगा वहीं गुरुग्राम का स्टार्टअप ग्रोफर्स कोविड-19 संकट से प्रभावित उद्योगों मसलन कपड़ा, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों से 2,000 अतिरिक्त लोगों की भर्ती करेगा। बिगबास्केट यह भर्ती उन 26 शहरों में करेगा जहां सामानों की डिलिवरी की जाती है।

बेंगलूरु के इस स्टार्टअप को डिलीवरी और वेयरहाउस स्टाफ की करीब 50 फीसदी कमी का सामना करना पड़ रहा है जिनमें से अधिकांश ने शुरुआत में पुलिस की सख्ती जबकि बाद में देश में कोरोनावायरस के मामले बढ़ने की वजह से लॉकडाउन की घोषणा होने के साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने घर में ही रहने को तरजीह दी। बिगबास्केट की उपाध्यक्ष (मानव संसाधन) तनूजा तिवारी ने कहा, 'कई श्रमिकों के घर में रहने या अपने गांवों और कस्बों में वापस जाने की वजह से अब हमें लोगों की जरूरत है जो ऑर्डर को पूरा करने के लिए सेवाएं दे सकें। इसी वजह से हम डिलिवरी और वेयरहाउस कर्मियों की भर्ती कर रहे हैं और यह दो तरीके से काम करेगा। हम ज्यादा ग्राहकों को सेवाएं दे पाएंगे और उन लोगों को रोजगार भी मुहैया कराएंगे जिन्हें इस समय काम की सबसे ज्यादा जरूरत है।'

ग्रोफर्स के 65 फीसदी वेयरहाउस स्टाफ काम कर रहे हैं। ग्रोफर्स के आपूर्ति चेन के प्रमुख रोहित शर्मा ने बताया, 'वेयरहाउस स्टाफ के आने-जाने के लिए इस वक्त सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी दिक्कतें हो रही हैं इसीलिए हमने अधिकारियों से अपने कर्मचारियों के लिए जरूरत के हिसाब से अपनी बस सेवा शुरू करने की इजाजत मांगी है। बसों को रोजाना सैनिटाइज किया जाता है और कर्मचारियों के लिए भी साफ-सफाई के पूरे मानदंडों का पालन किया जा रहा है।' ग्रोफर्स ने कहा कि यह दूसरे प्लेटफॉर्म मसलन जोमैटो के साथ भी सहयोग कर रही है ताकि उनकी डिलिवरी भी हो सके। कंपनी आकर्षक वेतन और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाओं का वादा भी कर रही है और उन्हें काम करने के लिए एक सुरक्षित माहौल देने का वादा भी कर रही है जिसमें नियमित आधार पर गोदामों, वितरण बक्से और अन्य उपकरणों को कीटाणुनाशक का इस्तेमाल करते हुए उसे सैनिटाइज करना शामिल है। इसके अलावा कर्मचारियों को दस्ताने और मास्क देने के साथ ही डिलिवरी करने वाले और वेयरहाउस कर्मचारियों की नियमित थर्मल स्कैनिंग भी कराएगी।

- 10,000 लोगों की भर्ती करेगी बिगबास्केट जबकि ग्रोफर्स 2,000 लोगों की भर्ती करने का मन बना रही है
- ऑनलाइन किराना स्टार्टअप सामानों की डिलिवरी और गोदाम की देखभाल करने वाले कर्मियों की भर्ती करना चाहते हैं जिनकी इस वक्त कमी हो गई है

कंपनी डिलिवरी की रफ्तार बढ़ाने के लिए कैब एग्रीगेटर्स, खुदरा विक्रेताओं और रेस्तरां संगठनों के साथ काम कर रही है ताकि अधिक लोगों की भर्ती की जा सके। इसने लॉकडाउन के दौरान ही ग्राहकों को उनके घर तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए उबर इंडिया के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी में उबर के ड्राइवर साझेदार बिगबास्केट को फिलहाल बेंगलूरु, हैदराबाद, चंडीगढ़ और नोएडा जैसे चार शहरों में सामानों की आपूर्ति कराने में मदद करेंगे। बिगबास्केट ने ग्राहकों और डिलिवरी अधिकारियों की सुरक्षा के लिहाज से कैशलेस भुगतान की सेवाएं शुरू की है। इसने दावा किया है कि इसने सरकारी अधिकारियों से पास का इंतजाम किया है ताकि कर्मचारियों को अपने काम पर जाने में कोई परेशानी न हो। फिलहाल बिगबास्केट रोजाना करीब 75,000 ऑर्डर पूरा कर रही है और यह अपनी कुल क्षमता के केवल 40 फीसदी का संचालन कर रही है। कंपनी ने कहा, 'हमने अपनी सर्वर क्षमता में 50 फीसदी का इजाफा किया है। इससे हमारे ऐप/ वेबसाइट को ज्यादा ग्राहकों के आने के बावजूद दिक्कत नहीं होगी और अधिक लोग ऑर्डर कर पाएंगे।'

निजी अस्पतालों को राज्यों ने किया सतर्क

पृष्ठ 1 का शेष

महाराष्ट्र में अब जिला अस्पतालों में भी इसकी व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम ठाणे, वाशी, कल्याण-डोंबीवली में करीब 30 सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के लिए 2,000 से अधिक विशेष बिस्तरों की व्यवस्था करने की योजना बना रहे हैं। इन अस्पतालों में इसके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं का प्रबंध किया जा रहा है।'

गुजरात में सरकार ने किसी भी निजी अस्पताल को अपने हाथों में नहीं लिया है लेकिन 131 अस्पतालों के इसके लिए तैयार रहने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरी तरह या आंशिक रूप से इन अस्पतालों को अपने हाथ में ले सकता हैं। फिलहाल सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन वार्ड हैं और अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट जैसे शहरों में और वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में 4,600 आइसोलेशन बिस्तर उपलब्ध हैं जबकि सरकार 2,700 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था कर रही है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर 131 निजी अस्पतालों में 1,000 विशेष बिस्तरों की पहचान की गई है। सरकारी अस्पतालों में अभी 1,100 वेंटिलेटर हैं और निजी अस्पतालों में अतिरिक्त 1,700 वेंटिलेटर की पहचान की गई है।

गुवाहाटी में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को सैनिटाइज किया गया

अधिकारी ने कहा, 'अगर जरूरत पड़ी तो और अधिक निजी अस्पतालों को जोड़ा जा सकता है जिससे आइसोलेशन बिस्तरों की संख्या 10 हजार से अधिक पहुंच सकती है।कर्नाटक सरकार भी इसके लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रही है जिसके तहत हर जिले में एक अस्पताल पूरी तरह कोविड-19 के मरीजों के लिए तैयार किया जाएगा। उस अस्पताल के मरीजों को पास के नजदीक के अस्पताल में भेजा जाएगा ताकि उन्हें किसी तरह के संक्रमण से बचाया जा सके। पश्चिम बंगाल में भी हर जिले में इसके लिए एक विशेष अस्पताल बनाया जाएगा। राजस्थान ने जयपुर में 84 निजी अस्पतालों में 9,000 से अधिक बिस्तर कोविड मरीजों के लिए रखे हैं।

फ्लिपकार्ट में नहीं होगी छंटनी व वेतन कटौती

पीरजादा अबरार

कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन से प्रभावित होने के बावजूद ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्याधिकारी कल्याण कृष्णमूर्ति ने अपने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि न तो कोई छंटनी होगी और न ही वेतन में किसी तरह की कटौती की जाएगी। कृष्णमूर्ति ने शुक्रवार को कंपनी के 8,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ वर्चुअल टाउनहॉल बैठक में हिस्सा लेते हुए कहा कि कर्मचारियों पर मौजूदा हालात का कोई असर नहीं पड़ेगा और उन्हें पहले से तय योजना के मुताबिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि फ्लिपकार्ट इंटर्नशिप समेत सभी तरह के जॉब ऑफर का सम्मान कर रही है। लॉकडाउन की वजह से ई-कॉमर्स कारोबार के बुरी तरह प्रभावित होने के बावजूद फ्लिपकार्ट दीर्घावधि नजरिया लेकर चल रही है। कृष्णमूर्ति ने कहा, 'संकट का वक्त अपना चरित्र, प्रतिबद्धता एवं दूरदर्शिता दिखाने का मौका होता है। मैं आप सबसे दीर्घकालिक सोच रखने की अपेक्षा करता हूं। अब हम भविष्य के लिए खुद का निर्माण करेंगे।' कृष्णमूर्ति ने सभी कर्मचारियों को सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा कि इस समय अधिक जिम्मेदार बनने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'मौका-परस्त न बनें। अपने साझेदारों एवं वेंडरों को न बदलें। ई-कॉमर्स की प्रगति के लिए वे अहम हैं और उसके लिए भरोसा जरूरी है। यह राष्ट्र-निर्माण में योगदान देने का वक्त है और हमें इस पर खरा उतरना है।'

महामारी के दौर में बफर स्टॉक की समीक्षा कितनी जरूरी ?

कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को अनाज मुहैया कराने में भरे हुए गोदामों का बड़ा हाथ है। क्या इस तर्क को बफर स्टॉक मानकों में सुधार के लिए किया जाना चाहिए ?

संजीव मुखर्जी

पिछले दिन का सिरदर्द अनजाने में ही आज का वरदान बन गया है। कोविड-19 महामारी फैलने के पहले अनाजों के ठसाठस भरे जिन गोदामों को वर्षों से विवाद का मुद्दा बनाया जाता रहा है उन्हीं गोदामों ने सरकार को यह सुविधा दी है कि देशबंदी में अपनी आजीविका गंवा चुके गरीबों का पेट भरने में इस अनाज का इस्तेमाल किया जा सके।

अगर केंद्र सरकार चाहे तो वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को अग्रिम तौर पर एक साल से भी अधिक वक्त का राशन दे सकती है। अभी तक उसने इन लोगों को मुफ्त में तीन महीने का राशन एडवांस में देने का फैसला किया है। इसके साथ प्रति परिवार एक किलो दाल भी दी जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के मुताबिक गत 10 मार्च को केंद्रीय पूल में भारत का गेहूं एवं चावल भंडार करीब 7.77 करोड़ टन था जिसमें 1.924 करोड़ टन धान भी शामिल है। अगर पिछले तीन साल के औसत इस्तेमाल को ध्यान में रखें तो एनएफएसए के सुचारु संचालन के लिए सालाना करीब 5.4 करोड़ टन अनाज की जरूरत होती है। यह स्थिति गेहूं खरीद का नया सीजन शुरू होने के पहले की है जो 2020-21 सत्र के लिए 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है।

अभी तक इस कानून के सभी लाभार्थियों को महीने में पांच किलो गेहूं या चावल काफी अधिक सब्सिडी पर दिया जाता है। चावल तीन रुपये प्रति किलो, गेहूं दो रुपये प्रति किलो और मोटे अनाज एक रुपये प्रति किलो के दाम पर दिए जाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नई घोषणा के बाद इन सभी लाभार्थियों को अगले तीन महीनों तक 10 किलो अतिरिक्त चावल या गेहूं मिलेगा।

भले ही ऐसा इरादतन नहीं हुआ है लेकिन इस कदम से गेहूं की नई फसल को रखने के लिए खाली गोदाम की जरूरी जगह भी पैदा हो सकेगी। हालांकि कोविड-19 के चलते मजदूरों की भारी किल्लत होने से इस सीजन की गेहूं कटाई का काम देर से ही हो पाएगा।

यह मानकर चलते हैं कि अप्रैल महीने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से खाद्यान्न का उठाव फरवरी 2020 के स्तर पर ही बना रहेगा। एक आकलन से पता चलता है कि सामान्य स्थितियों में करीब 93 लाख टन गेहूं और चावल की सार्वजनिक भंडारगृहों से निकासी होती। आवंटन को दोगुना करने के सरकारी फैसले के बाद करीब 1.9 करोड़ टन अनाज गोदामों से बाहर निकलने की संभावना है।

अनाज भंडार की अच्छी स्थिति होने और केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों की तरफ से भी गरीबों के लिए नि:शुल्क राशन देने की घोषणाओं के बाद एक बार फिर वह बहस खड़ी हुई है कि क्या भारत को कोविड-19 महामारी जैसे संकटपूर्ण हालात से निपटने के लिए अपने तिमाही अनाज भंडार मानकों को बढ़ाने की जरूरत है? इस बात को लेकर लंबे समय से अलग-अलग राय रही है। दरअसल बड़ा बफर स्टॉक बनाए रखने की ऊंची लागत और अधिक भंडारण की वजह से होने वाले नुकसान जैसे मुद्दों को लेकर मतभेद रहे हैं। यह स्थिति नकदी की भारी कमी से जूझ रही सरकार के लिए वास्तव में एक चिंता की बात है। एफसीआई ने अपना परिचालन जारी रखने के लिए पहले ही लघु बचत पूल से उधारी लेने का अप्रत्याशित कदम उठाया हुआ है।

> एफसीआई के मुताबिक गत 10 मार्च को केंद्रीय पूल में भारत का गेहूं एवं चावल भंडार करीब 7.77 करोड़ टन था

केंद्र सरकार हरेक पांच साल के बाद खाद्यान्न के बफर स्टॉक संबंधी मानकों की समीक्षा करती है लेकिन ऐसी पिछली समीक्षा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के पहले ही की गई थी। मौजूदा मानकों के हिसाब से सरकार को मोटे तौर पर 4.5 महीने का पीडीएस अनाज हर साल 1 अप्रैल को बफर स्टॉक के तौर पर रखना होता है। 1 जुलाई को यह मात्रा 9.2 महीनों के पीडीएस अनाज की रहती है जबकि 1 अक्टूबर को सात महीने और 1 जनवरी को करीब पांच महीनों का अनाज सरकार को बफर रखना होता है।

रमेश चंद की अगुआई वाले पैनल ने वर्ष 2013 में बफर स्टॉक की तिमाही सीमा बढ़ाने की अनुशंसा की थी

बीते दशक में चर्चा का विषय यह रहा है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये सीधे लाभार्थी के खाते में अनाज खरीद के लिए पैसे भेज दिए जाएं या फिर उसे पहले की तरह अनाज ही बांटा जाए। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'सरकार ने पिछली बार बफर स्टॉक सीमा बढ़ाने से इसलिए इनकार कर दिया था कि पीडीएस के तहत अनाज के बजाय नकद पैसे देने की तरफ रुझान बढ़ेगा।' लेकिन डीबीटी की तरफ तेजी से नहीं बढ़ने से यही लगता है कि बफर स्टॉक की सीमा बढ़ाना ही इकलौता समाधान है। रमेश चंद की अगुआई वाले पैनल ने ही 2013 में बफर स्टॉक की तिमाही सीमा बढ़ाने की अनुशंसा की थी।

कृषि लागत एवं कीमत आयोग के पूर्व चेयरमैन और इक्रियर संस्थान में कृषि के इन्फोसिस चेयर प्रोफेसर अशोक गुलाटी का सुझाव है कि पीडीएस लाभार्थियों को नकदी पैसा देना अब भी अनाज देने से कहीं बेहतर विकल्प है। उनका कहना है कि बफर स्टॉक के मानक इस आधार पर तय किए गए थे कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पीडीएस के जरिये खाद्यान्न का वार्षिक उठाव कितना होगा? इस कानून के तहत पिछले तीन वर्षों में हुआ अनाज उठाव दिखाता है कि यह सोच से काफी कम रहा है। गुलाटी सवालिया लहजे में कहते हैं, 'ऐसी स्थिति में बफर स्टॉक की सीमा बढ़ाने या उसके संशोधन की जरूरत ही कहां रह जाती है?'

गुलाटी की मानें तो 2013 के बफर मानक इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे कि केंद्र सरकार को सालाना करीब 6.12 करोड़ टन अनाज की जरूरत एनएफएसए के तहत होगी। लेकिन पिछले तीन वर्षों का उठान महज 5.3-5.5 करोड़ टन ही रहा है। इस हिसाब से देखें तो बफर मानकों में सुधार की कोई जरूरत नहीं है।

वह कहते हैं कि मौजूदा हालात में भी अगर किसी व्यक्ति के पास अनाज के बजाय नकदी होती तो वह उससे कहीं पर भी अपना पेट भर सकता था। वह कहते हैं, 'अगर हम उन्हें गेहूं ही दें दे तो वह चक्कियों के नहीं चल पाने पर क्या कर पाएगा।'

सच तो यह है कि भोजन मिल पाना सबसे अहम है। इसीलिए खाद्य एवं कृषि के पूर्व सचिव शिराज हुसैन ने शहरी इलाकों में मजदूरों एवं दैनिक कामगारों के लिए अधिक संख्या में सामुदायिक रसोईघर बनाने की जरूरत पर बल दिया है। ऐसा होने पर शहरी उपभोक्ताओं के लिए प्रसंस्कृत खाद्य के सुचारू संचालन के लिए वितरण नेटवर्क की बाधाएं दूर की जा सकेंगी। हुसैन कहते हैं, 'कोविड-19 किसी की जिंदगी में कभी एक बार आने वाला संकट है। लिहाजा इसके आधार पर कोई योजना बनाना लंबी अवधि में नहीं संभव है। हमें भंडार बढ़ाने के बजाय सुचारु आपूर्ति श्रृंखलाओं की जरूरत है जो मौजूदा अनाज भंडार का ही सही से वितरण कर सकें।'

संक्षेप में, कोविड-19 महामारी से उपजे हालात को आधार बनाकर बफर स्टॉक के मानक बढ़ाना लंबे समय में कोई बढ़िया सोच नहीं होगी।